घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 168- सोमवार 20 - अप्रैल 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

तमिलनाडु में पटाखा फैक्ट्री में धमाका,18 की मौत

तमिलनाडु,19 अप्रैल 2026। तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले के पास कट्टनारपट्टी स्थित 'वनजा पटाखा फैक्ट्री' में रविवार को धमाके से भीषण हादसा हो गया। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस घटना पर दुख जताया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि विरुधुनगर जिले में पटाखा कारखाने में हुए विस्फोट में कई लोगों की मृत्यु की दुखद खबर से गहरा दुख हुआ है। मृतकों के परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। जानकारी के मुताबिक, इस फैक्ट्री का मालिकाना हक गोविंदनाल्लूर निवासी मुथु मानिकम के पास है और यह एक वैध आरडीओ लाइसेंस के तहत संचालित हो रही थी। फैक्ट्री परिसर में 30 से अधिक कमरे बने हुए हैं और यहां 50 से ज्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं। रविवार को जब लगभग 30 कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर

मौजूद थे, तभी अचानक एक जोरदार विस्फोट हुआ। इस धमाके से फैक्ट्री के कम से कम चार कमरों को भारी नुकसान पहुंचा और देखते ही देखते वहां अफरा-तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद करीब एक घंटे से अधिक समय तक आग पर काबू पाने का प्रयास किया। कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया, लेकिन तब तक नुकसान काफी गंभीर हो चुका था। हादसे के समय फैक्ट्री में 30 से अधिक लोग मौजूद थे, जिनमें से कई मलबे के नीचे दब गए। बचाव दल ने तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया और मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश जारी रखी। अब तक लगभग 18 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि अन्य लापता लोगों की तलाश जारी है। इस दर्दनाक घटना के बाद प्रशासन और पुलिस विभाग भी हरकत में आ गया है। पुलिस अधीक्षक (एसपी) श्रीनाथ स्वयं मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं और पूरे मामले की गहन जांच के आदेश दिए गए हैं।

सीएम स्टालिन ने जताया दुःख

इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि यह घटना बेहद दु:खद है और उन्हें इससे गहरा आघात पहुंचा है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट कीं और कहा कि सरकार इस कठिन समय में उनके साथ खड़ी है। साथ ही प्रशासन को राहत और सहायता कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने मंत्री केकेएसएसआर रामचंद्रन और थंगम थेन्नारासु से तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव कार्यों में तेजी लाने और उनकी निगरानी करने तथा प्रभावित परिवारों को सांत्वना देने का अनुरोध किया है। इस घटना की सूचना मिलते ही मैंने जिला कलेक्टर से संपर्क किया और उन्हें सभी आवश्यक सहायता समन्वय करने का निर्देश दिया है।

राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने भी जताया दुःख

राष्ट्रपति ने भी इस हादसे को बेहद दु:खद बताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने भी घटना पर शोक जताते हुए कहा कि यह हादसा बेहद पीड़ादायक है। उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। दोनों नेताओं ने इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ खड़े रहने का भरोसा दिया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की।

मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की तैयारी में विपक्ष,दोबारा नोटिस देंगे

मार्च में एक बार खारिज हो चुका..अब 200 सांसदों का समर्थन जुटाएंगे

नई दिल्ली,19 अप्रैल 2026। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए विपक्ष एक बार फिर कोशिश में जुटा है। सूत्रों के अनुसार, कई विपक्षी दलों के नेता आपस में बातचीत कर रहे हैं। करीब पांच सीनियर लीडर एक नए नोटिस का मसौदा तैयार करने पर काम कर रहे हैं,ताकि हटाने की कार्यवाही शुरू की जा सके। इससे पहले मार्च में विपक्ष ने ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए संसद में नोटिस दिया था। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने इन नोटिसों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लगाए गए आरोप उन्हें टाने के लिए आवश्यक उच्च संवैधानिक मानदंडों को पूरा नहीं करते।

विपक्ष ने 200 हस्ताक्षर हासिल करने का लक्ष्य रखा : नए नोटिस में विपक्ष कम से कम 200 सांसदों का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है। इसकी बड़ी वजह हाल ही में लोकसभा में गिरा महिला आरक्षण संशोधन बिल है। लोकसभा में शुक्रवार को संविधान में 131वां संशोधन बिल वोटिंग के बाद गिर गया। बिल के खिलाफ 230 सांसदों ने वोट डाला था।

नियम के अनुसार 100 सांसदों के दस्तखत जरूरी : लोकसभा में सीईसी को हटाने के प्रस्ताव के लिए कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। राज्यसभा में इसके लिए कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी तरीके से हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। अन्य चुनाव आयुक्तों को हटाने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश जरूरी होती है।

बांकुरा में गरजे पीएम मोदी,कहा...टीएमसी के गुंडों को 4 मई से पहले आत्मसमर्पण करने का आखिरी मौका

कोलकाता,19 अप्रैल 2026। पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में प्रधानमंत्री मोदी राज्य के बांकुरा में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने राज्य की सत्ताधारी दल टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी की 'निर्मम सरकार' के खिलाफ लोगों के गुस्से में जोश झलक रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि भाजपा महिला सशक्तिकरण,उनकी सुरक्षा और संरक्षा का पर्याय है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि देश के विकास को सुनिश्चित करने के लिए हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक महिलाएं राजनीति में शामिल हों।

टीएमसी के गुंडों को आत्मसमर्पण करने का आखिरी मौका : मोदी

जनसभा में पीएम मोदी ने कहा कि मैं टीएमसी के गुंडों को चुनाव से पहले पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने का आखिरी मौका देता हूं, क्योंकि 4 मई को परिणाम आने के बाद किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।

टीएमसी ने कांग्रेस के साथ साजिश रची : प्रधानमंत्री मोदी

पीएम मोदी ने आगे कहा कि 2029 में महिलाओं के लिए आरक्षण विधेयक पारित होने से रोकने के लिए टीएमसी ने कांग्रेस के साथ साजिश रची,उन्हें कांग्रेस द्वारा दंडित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि टीएमसी और कांग्रेस दोनों आदिवासी विरोधी हैं,और राष्ट्रपति चुनाव के दौरान द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए थे। टीएमसी,जो घुसपैठियों को फायदा पहुंचाने के लिए हर कानून तोड़ती है और धर्म के आधार पर आरक्षण देती है, महिला सशक्तिकरण का विरोध करती है। टीएमसी कुर्मी समुदाय की शिकायतों को नहीं सुनती, बल्कि अपने वोट बैंक को आरक्षण देना चाहती है।

प्रधानमंत्री ने इस दौरान कहा कि इस साल के बंगाल चुनाव ऐतिहासिक होंगे क्योंकि जनता टीएमसी के 'भय' को खत्म करेगी और भाजपा के 'भरोसे' को जनादेश देगी। बांकुरा में चुनावी रैली में मोदी ने कहा कि अगर बंगाल में भाजपा सत्ता में आती है,तो वह पीएमएवाई के तहत महिलाओं को घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान करेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'अगर बंगाल में भाजपा की सरकार बनती है, तो महिलाओं को पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। अगर किसी महिला के परिवार में किसी को गुर्दे की बीमारी है, तो उन्हें सरकारी अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस की सुविधा मिलेगी। इसका एक भी रुपया खर्च नहीं होगा। बंगाल की बहनों को हर साल 36,000 रुपये मिलेंगे। गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये दिए जाएंगे। केंद्र सरकार भी बहनों को संतान प्राप्ति के बाद उनकी बेटियों की शिक्षा के लिए 5,000 रुपये देगी। कुल मिलाकर 50,000 रुपये दिए जाएंगे।

अक्षय तृतीया पर चारधाम यात्रा की शुरुआत

गंगोत्री-यमुनोत्री धाम के कपाट खुले जय मां गंगा-यमुना' के गूंजे जयघोष

नई दिल्ली,19 अप्रैल 2026। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर रविवार से चारधाम यात्रा का विधिवत शुभारंभ हो गया। वैदिक मंत्रोच्चारण, धार्मिक अनुष्ठानों और 'जय मां गंगा-यमुना' के जयघोष के बीच गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इस शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहे और उन्होंने इस दिव्य क्षण का साक्षी बनकर यात्रा के महत्व को और बढ़ाया। गंगोत्री धाम में कपाट खुलने के समय हजारों श्रद्धालु मंदिर परिसर में मौजूद रहे। पूरा वातावरण 'हर-हर गंगे' और 'मां गंगा की जय' के नारों से गूंज उठा। निर्धारित शुभ मुहूर्त के अनुसार दोपहर 12:15 बजे कपाट खोले गए। इस दौरान श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा की गई, जिससे माहौल और भी भक्तिमय हो गया। इससे पहले सुबह तड़के मां गंगा की उत्सव डोली भैरव घाटी से गंगोत्री के लिए रवाना हुई। भैरव घाटी में विशेष पूजा-अर्चना के बाद डोली यात्रा आगे बढ़ी। मंदिर समिति के अनुसार विधि-विधान से गंगा पूजन, गंगा सहस्रनाम पाठ और विशेष अनुष्ठान संपन्न कर कपाट खोले गए। पहले ही दिन हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त किया।

सीएम ममता बनर्जी का केंद्र पर आरोप...

प्रधानमंत्री मोदी ने देश को किया गुमराह

कोलकाता,19 अप्रैल 2026। महिला आरक्षण के मुद्दे पर बहस लगातार जारी है। इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने महिला आरक्षण बिल को लेकर देश को गुमराह किया है। ममता बनर्जी ने इसे गहरी निराशाजनक स्थिति बताया और कहा कि देश को सच्चाई बताने के बजाय गलत तरीके से पेश किया गया। ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस हमेशा से महिलाओं की राजनीति में ज्यादा भागीदारी की समर्थक रही है। उन्होंने आंकड़े देते हुए बताया कि उनकी पार्टी में लोकसभा और राज्य विधानसभा दोनों में महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा है। लोकसभा में उनकी पार्टी के करीब 37.9 प्रतिशत सांसद महिलाएं हैं, जबकि राज्यसभा में लगभग 46 प्रतिशत महिला सदस्य हैं। उन्होंने साफ कहा

कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, बल्कि जिस तरीके से केंद्र सरकार इस मुद्दे के साथ 'परिसीमन' को जोड़ रही है, उसका विरोध कर रही है। ममता का आरोप है कि सरकार अपने राजनीतिक फायदे के लिए महिलाओं के मुद्दे को ढाल बना रही है। यह बयान उस समय आया है जब हाल ही में लोकसभा में 2029 से लागू होने वाले 33 प्रतिशत महिला आरक्षण से जुड़ा बिल पास नहीं हो सका। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर निशाना साधते हुए कहा था कि देश की महिलाएं उन्हें 'कन्या भ्रूण हत्या जैसे पाप' के लिए सजा देंगी। इस पूरे मामले में अब राजनीति और तेज हो गई है। एक तरफ केंद्र सरकार विपक्ष पर महिला विरोधी होने का आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष, खासकर ममता बनर्जी, सरकार पर राजनीतिक फायदा उठाने और असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगा रही हैं। आने वाले समय में यह मुद्दा और बड़ा राजनीतिक विवाद बन सकता है।

पंजाब में बेअदबी पर सख्त कानून का रास्ता साफ राज्यपाल ने बिल को दी मंजूरी

नई दिल्ली,19 अप्रैल 2026। पंजाब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के खिलाफ सख्त कानून का रास्ता साफ हो गया है। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने 'जागृत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) बिल, 2026' पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रविवार को कहा कि यह बड़ा कदम है और उन्होंने वाहेगुरु का आभार जताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्हें यह सेवा करने का अवसर मिला, इसके लिए वह कृतज्ञ हैं और समूची सिख संगत का धन्यवाद करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्य धर्मों के लोगों से बातचीत कर जल्द ही उनके लिए भी इसी तरह का कानून लाया जाएगा। नए कानून के तहत बेअदबी से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों को अपराध की श्रेणी में रखा गया है, जैसे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 'स्वरूप' (पवित्र ग्रंथ) को जानबूझकर फाड़ना, जलाना या किसी भी तरह से खंडित करना, पवित्र ग्रंथ पर थूकना, उसे गंदे हाथों से छूना या किसी ऐसी जगह रखना।

मध्य प्रदेश के अनूपपुर में ट्रैक्टर पलटने से 4 दोस्तों की मौत,गांव में पसरा मातम

अनूपपुर,19 अप्रैल 2026। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में रविवार सुबह एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गया, जिससे सभी युवक उसके नीचे दब गए। बताया गया कि डिंडौरी जिले के रहने वाले चार दोस्त ट्रैक्टर से गिट्टी लेने जा रहे थे, तभी रास्ते में उनका वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया और सभी की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार डिंडौरी जिले के करंजिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भीमकुंडी के रहने वाले चार युवक ट्रैक्टर लेकर अनूपपुर के पौनी गांव की ओर जा रहे थे। उनका उद्देश्य क्रेशर से गिट्टी लाना था। सुबह करीब छह बजे करन पठार थाना क्षेत्र के ठाड़ पाथर के पास अचानक ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया। देखते ही देखते ट्रैक्टर सड़क से नीचे उतरकर गहरे गड्ढे में जा पलटा। हादसा इतना भीषण था कि ट्रैक्टर और ट्रॉली के नीचे दबते ही सभी युवकों की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन स्थिति बेहद गंभीर थी। ट्रैक्टर का

इंजन और भारी हिस्सा युवकों के ऊपर ही था, जिससे उन्हें निकालना बेहद मुश्किल हो रहा था। इसके बाद पुलिस ने जेसीबी मशीन बुलवाई और कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर को हटाकर शवों को बाहर निकाला गया। इस हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान अंकुश उइके (24), ब्रजेश पेंदो (18), रवींद्र कुमार गोयल और 15 वर्षीय प्रकाश मार्को के रूप में हुई है। इनमें से एक युवक नाबालिग भी था। सभी मृतक भीमकुंडी गांव के निवासी थे और आपस में अच्छे दोस्त बताए जा रहे हैं। घटना से गांव में शोक की लहर दौड़ गई। चार युवकों की मौत से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है।

चुनाव से पहले ईडी का बड़ा एक्शन, ममता के करीबी डीसीपी के घर छापा

नई दिल्ली,19 अप्रैल 2026। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में रविवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। ईडी की टीम ने बल्लीगंज स्थित कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास के आवास पर छापा मारा। इसके अलावा बेहाला इलाके में सन

एंटरप्राइज के प्रबंध निदेशक जॉय कामदार के घर पर भी कार्रवाई की गई। सूत्रों के अनुसार,गोलपार्क स्थित शांतनु सिन्हा के आवास के साथ ही पास में मौजूद एक सरकारी प्रशिक्षण केंद्र को भी जांच के दायरे में लिया गया, हालांकि वह केंद्र सुबह से बंद बताया गया। शांतनु सिन्हा को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का करीबी अधिकारी माना जाता है। हाल ही में उन्हें राज्य सरकार के धरने के दौरान मुख्यमंत्री के मंच पर भी देखा गया था। उस समय कोलकाता पुलिस ने स्पष्ट किया था कि वे सुरक्षा व्यवस्था के तहत वहां मौजूद थे।

कावेरी नदी में डूबने से 6 लोगों की मौत उर्स कार्यक्रम के दौरान हुआ हादसा

मैसूरु,19 अप्रैल 2026। कर्नाटक के मैसूरु जिले के केआर नगर क्षेत्र में रविवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें कावेरी नदी में डूबने से छह लोगों की मौत हो गई। यह घटना अर्केश्वर मंदिर के पास स्थित पुराने एडथोरे अर्केश्वर स्वामी मंदिर क्षेत्र में हुई। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस घटना पर शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपये मुआवजे की घोषणा की है। यहां स्थित हजरत खादर लिंगवल्ली दरगाह में उर्स कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम परिवार शामिल होने पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान आठ लोग कावेरी नदी में उतरे और तैरने का प्रयास किया, लेकिन नदी की तेज धारा और गहराई के कारण छह लोग पानी में फंस गए और बाहर नहीं निकल सके। स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया और दो लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

घायलों को आगे के इलाज के लिए मैसूरु के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान मैसूरु के 5 वर्षीय उमर,बेंगलुरु की 13 वर्षीय ऐमन,केआर नगर के 13 वर्षीय अफीफ,बेंगलुरु के 23 वर्षीय यासीन,बेंगलुरु की 22 वर्षीय नेहा और ऊटी की 30 वर्षीय फातिमा के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही केआर नगर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।

उज्जैन में मॉडल हर्षा रिछारिया ने लिया संन्यास

अब स्वामी हर्षानंद गिरि के नाम से जानी जाएंगी,पिंडदान के साथ त्यागा पिछला जीवन

उज्जैन,19 अप्रैल 2026। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर और मॉडल हर्षा रिछारिया ने रविवार को अक्षय तृतीया पर संन्यास ले लिया। उन्हें उज्जैन के मौनी तीर्थ आश्रम में पंचायती निरंजनी अखाड़ा के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी सुमनानंद गिरि महाराज ने संन्यास दीक्षा दी। संन्यास परंपरा के अनुसार, उन्हें शिखा और दंड त्याग की विधि कराई गई। साथ ही तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म भी कराए गए, जो पूर्व जीवन के त्याग और नए आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत का प्रतीक माने जाते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों के बाद हर्षा रिछारिया ने

संन्यास ग्रहण किया और उन्हें नया नाम स्वामी हर्षानंद गिरि दिया गया। इस मौके पर स्वामी हर्षानंद गिरि ने कहा कि यह उनके जीवन का नया अध्याय है। उन्होंने गुरुदेव के मार्गदर्शन में संन्यास का मार्ग अपनाया है और संकल्प लिया है कि वे अपना जीवन धर्म, संस्कृति और समाज की सेवा में समर्पित करेंगी और संन्यास की मर्यादा का पालन करेंगी।

संन्यास दीक्षा एक गहन और अनुशासित प्रक्रिया : महामंडलेश्वर स्वामी सुमनानंद गिरि महाराज ने कहा- संन्यास दीक्षा एक गहन और अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें व्यक्ति अपने पूर्व जीवन का त्याग कर आध्यात्मिक पथ पर चलता है। मेरा सभी संन्यासियों से यही आग्रह रहता है कि वे संन्यास की गरिमा को कभी कलंकित नहीं होने दें। एक संन्यासी के आचरण का प्रभाव पूरे समाज और संन्यास परंपरा पर पड़ता है,इसलिए विधि-विधान और मर्यादा का पालन अत्यंत आवश्यक है। रिछारिया का परिवार मूलतः था उत्तर प्रदेश के झांसी का रहने वाला है। उनके पिता दिनेश बस कंडक्टर और मां किरण रिछारिया बुटीक चलाती हैं। एक भाई कपिल है जो प्राइवेट जॉब करता है। पूरा परिवार भोपाल में रहता है।

संपादकीय

संघर्ष के दौर में ऊर्जा

ईरान के खिलाफ विनाशकारी अमेरिका-इजरायल संघर्ष ने दुनिया भर में ऊर्जा आपूर्ति को बाधित कर दिया है। अमीर और गरीब दोनों तरह के देशों की सरकारें अपने लोगों को आने वाले भीषण समय के बारे में सचेत कर रही हैं,जैसा इस पीढ़ी ने पहले कभी नहीं देखा। ऊर्जा/ईंधन की अविश्वसनीय कमी,राशनिंग और यहां तक कि कारों और हवाई जहाजों के ईंधन खत्म होने की आशंका। सवाल यह है कि भविष्य का ऊर्जा मानचित्र कैसा दिखेगा?

विनाश और मानवीय पीड़ा

जैसा कि मैं यह पूछ रही हूं,मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि उन हत्याओं,हजारों जानों के नुकसान और उस संवेदनहीन विनाश को हल्के में न लें जिसे हम अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। इस ऊर्जा व्यवधान द्वारा दुनिया में लाए गए वास्तविक दर्द को भी कम करके न आंकें। कई देश रसोई ईंधन (एलपीजी) की कमी का सामना कर रहे हैं,और परिवार इसे किसी भी कीमत पर हासिल करने के लिए अपनी आय का बड़ा हिस्सा खर्च कर रहे हैं। ईंधन स्टेशनों पर लंबी कतारें सामान्य हो रही हैं-जो फिर से उन लागतों को बढ़ा रही हैं जिन्हें लोग मुश्किल से वहन कर सकते हैं।

अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

ज्यादातर देशों में, विशेष रूप से हमारी दुनिया में, ईंधन आयात व्यापार घाटे पर सबसे अधिक भार है और इस स्थिति में,तेल की बढ़ती कीमतों का अर्थव्यवस्थाओं पर अपंग कर देने वाला प्रभाव पड़ता है। वहीं वैश्विक उर्वरक आपूर्ति में आसन्न कमी से किसानों पर भारी मार पड़ने की आशंका है-वे जो पहले से ही जलवायु परिवर्तन से प्रेरित चरम मौसम और विकृत वैश्विक खाद्य कीमतों से जूझ रहे हैं। कुल मिलाकर,दुनिया घुटनों पर है-पसंद से नहीं, बल्कि ईरान के खिलाफ इस संवेदनहीन अमेरिका-इजरायल संघर्ष के प्रति अपनी डरपोक और दयनीय प्रतिक्रिया के कारण। नियम-आधारित व्यवस्था और उसकी सारी नैतिकता तार-तार हो चुकी है।

ऊर्जा संक्रमण की गति

यह हमारे सामने सवाल छोड़ता है कि इस झटके का ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस अशोभनीय संघर्ष से पहले भी दुनिया ऊर्जा संक्रमण के बीच में थी-बिजली के लिए कोयले को लगातार नवीकरणीय ऊर्जा से बदलना और वाहनों में पेट्रोल और डीजल के उपयोग को विस्थापित करना। अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की मार्च 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, 2025 के अंत तक, दुनिया की स्थापित बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी लगभग 50 प्रतिशत थी।

विकासशील देशों का नेतृत्व

दिलचस्प बात यह है कि यह ऊर्जा संक्रमण केवल वहां नहीं हो रहा था जहां उम्मीद की जा सकती थी-जैसे चीन या यूरोप। थिंक टैंक एंबर की एक रिपोर्ट में पाया गया कि 74 सबसे जलवायु-संवेदनशील देश इलेक्ट्रो-टेक को तेजी से अपना रहे थे,इसलिए नहीं कि वे जलवायु परिवर्तन के प्रति चिंतित थे,बल्कि इसलिए कि यह तेज,सस्ता और अधिक विश्वसनीय था। ये देश जीवाश्म ईंधन को छोड़कर सीधे नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ सकते हैं। रिपोर्ट कहती है, सौर उत्पादन में नामीबिया और टोगो, बैटरी बिक्री में जार्डन और किर्गिस्तान,और ईवी अपनाने में नेपाल और श्रीलंका आगे हैं।

भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा

वर्तमान व्यवधान ने ऊर्जा आयात की लागत बढ़ा दी है और देशों को ऊर्जा सुरक्षा की आवश्यकता के प्रति जागरूक कर दिया है। तेल और गैस के बाजारों को हासिल करने के लिए फिर से होड़ मची है। यह देशों को अपने स्वयं के संसाधनों-कोयला से लेकर चारकोल तक- का अधिक उपयोग करने के लिए प्रेरित कर सकता है, जो दोनों ही प्रदूषणकारी हैं। होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने से वैश्विक प्रवाह का लगभग 20 प्रतिशत बाधित हुआ है। इसका मतलब यह हो सकता है कि सस्ते और प्रचुर मात्रा में जीवाश्म ईंधन का समय समाप्त हो गया है।

एक विभाजित दुनिया

अब स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण का तर्क राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा में निहित होगा। जैसा कि मैं यह लिख रही हूं,मुझे दुख के साथ स्वीकार करना चाहिए कि भविष्य आसान नहीं होने वाला है। यह वर्तमान समय मुझे बताता है कि एक वैश्विक समाज के रूप में हम पीछे हटे हैं। मानवीय विनाश और पतन के इन खंडहरों से टुकड़ों को समेटना कठिन होगा। ऐसी टूटी और विभाजित दुनिया में जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक समस्याओं को हल करना हमारे लिए कठिन होगा!

अनमोल वचन

***कामयाब लोग अपने फ़ैसले से दुनिया बदल देते है और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फ़ैसले बदल लेते है।**

***पंछी कभी अपने बच्चों के भविष्य**

नारी शक्ति या सत्ता का नया मुखौटा?

आरक्षण,नैतिकता और राजनीति का असली सवाल

प्रियंका सौरभ
हिसार,हरियाणा

देश में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ, तो इसे ऐतिहासिक बताया गया,संसद में तालियां बजीं और महिला सशक्तिकरण के नए युग की घोषणा की गई,लेकिन इस पूरे उत्सव के बीच एक असहज सवाल लगातार सिर उठाता रहा–क्या सच में महिलाओं के लिए राजनीति के दरवाजे खुले हैं,या केवल एक नया प्रतीकात्मक फ्रेम तैयार किया गया है जिसमें वही पुरानी सत्ता की तस्वीर फिट कर दी जाएगी। भारतीय राजनीति का चरित्र आदर्शवाद जितना नहीं,उससे कहीं अधिक यथार्थवादी और कई बार कठोर भी रहा है, जहां सिद्धांतों से ज्यादा समीकरण काम करते हैं और नैतिकता अक्सर सत्ता की सुविधा के हिसाब से बदलती रहती है, ऐसे में यह उम्मीद करना कि केवल आरक्षण से व्यवस्था ,का चरित्र बदल जाएगा,शायद एक भोला विश्वास हो सकता है। महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़नी चाहिए, यह एक बुनियादी लोक तांत्रिक आवश्यकता है,लेकिन सवाल यह है कि क्या यह भागीदारी वास्तविक सशक्तिकरण में बदलेगी या फिर वही सत्ता संरचना उन्हें अपने ढांचे में ढाल लेगी, जैसा वह हर नए प्रवेशकर्ता के साथ करती आई है। राजनीति में प्रवेश का रास्ता आज भी बेहद जटिल है,जहां परिवार,पूंजी,संपर्क और दलगत निष्ठा का दबाव काम करता है,और महिलाओं के लिए यह राह और अधिक कठिन हो जाती है क्योंकि उन्हें सामाजिक बंधनों, चरित्र पर सवाल और अवसरों की कमी जैसे अतिरिक्त अवरोधों से गुजरना पड़ता है, ऐसे में यह मान लेना कि हर महिला जो आगे बढ़ेगी वह केवल समझौतों के रास्ते ही बढ़ेगी,यह न केवल सरलीकरण है बल्कि उन हजारों महिलाओं के संघर्ष का अपमान भी है जो अपनी मेहनत और योग्यता से जगह बना रही हैं।

असल समस्या यह है कि जिस सिस्टम में यह आरक्षण लागू हो रहा है,वह खुद पारदर्शी और निष्पक्ष नहीं है,राजनीतिक दलों के भीतर लोकतंत्र की कमी,टिकट वितरण में अपारदर्शिता और नेतृत्व का केंद्रीकरण यह सुनिश्चित करता है कि अवसर योग्यता से अधिक नजदीकियों के आधार पर बांटे जाते हैं,ऐसे में अगर

महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित भी हो जाती हैं,तो यह जरूरी नहीं कि वे वास्तव में स्वतंत्र और सशक्त प्रतिनिधि बनकर उभरें, बल्कि यह भी संभव है कि वे उसी सत्ता खेल का हिस्सा बन जाएं जहां निर्णय कहीं और होते हैं और चेहरे कहीं और दिखते हैं। यही कारण है कि इस कानून को लेकर आशा के साथ-साथ आशंका भी स्वाभाविक है, क्योंकि अगर संरचना नहीं बदली,तो परिणाम भी वैसा ही रहेगा जैसा अब तक रहा है। राजनीति में नैतिकता का सवाल भी इस बहस के केंद्र में है, क्योंकि सत्ता के गलियारों में संपर्क और समझौते की संस्कृति लंबे समय से मौजूद है, और यह केवल महिलाओं तक सीमित नहीं है,बल्कि पूरे सिस्टम में फैली हुई है, ऐसे में अगर इस संस्कृति को चुनौती नहीं दी गई, तो आरक्षण भी उसी ढांचे में समाहित होकर अपना मूल उद्देश्य खो सकता है।

यह भी समझना जरूरी है कि प्रतिनिधित्व बढ़ाने से परिवर्तन की गारंटी नहीं मिलती,कई बार नए लोग भी पुराने ढर्रे पर चलने लगते हैं क्योंकि व्यवस्था उन्हें वैसा बनने के लिए मजबूर करती है,इसलिए किसी भी सुधार का मूल्यांकन केवल संख्या के आधार पर नहीं,बल्कि उसके प्रभाव के आधार पर किया जाना चाहिए,क्या महिलाओं की संख्या बढ़ने से नीतियों में संवेदनशीलता आएगी, क्या सामाजिक मुद्दों को प्राथमिकता मिलेगी,या फिर राजनीति केवल नए चेहरों के साथ पुरानी दिशा में चलती रहेगी,यह एक खुला सवाल है जिसका जवाब समय ही देगा। इस पूरे परिदृश्य में सबसे महत्वपूर्ण तत्व जवाबदेही है, अगर कोई भी व्यक्ति,चाहे वह पुरुष हो या महिला,सत्ता का दुरुपयोग करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हमारे संस्थान स्वतंत्र और मजबूत हों,जो बिना राजनीतिक दबाव के काम कर सकें, दुर्भाग्य से आज अपराध और राजनीति का गठजोड़ एक गंभीर समस्या बन चुका है,जहां कई मामलों में आरोपियों को संरक्षण मिलता है और पीड़ितों की आवाज दबा दी जाती है, ऐसे में यह उम्मीद करना कि केवल आरक्षण इस समस्या को खत्म कर देगा, यथार्थवादी नहीं है।

समाधान के रूप में हमें व्यापक सुधारों की जरूरत है,राजनीतिक दलों के भीतर पारदर्शिता लानी होगी,टिकट वितरण के स्पष्ट और निष्पक्ष मानदंड तय करने होंगे,महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वतंत्र शिकायत तंत्र विकसित करना होगा ताकि वे बिना डर के अपनी बात रख सकें,साथ ही उन्हें केवल प्रतीकात्मक प्रतिनिधि के रूप में नहीं बल्कि सक्षम और प्रशिक्षित नेतृत्व के रूप में तैयार करना होगा,इसके लिए राजनीतिक शिक्षा,संसाधन और संस्थागत समर्थन जरूरी है, और सबसे महत्वपूर्ण,समाज की मानसिकता में बदलाव लाना होगा क्योंकि जब तक महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं मिलेगा,तब तक कोई भी कानून अपने उद्देश्य को पूरी तरह हासिल नहीं कर पाएगा। अंततः यह समझना होगा कि देश की समस्याओं का समाधान केवल सीटों की संख्या बढ़ाने में नहीं है, बल्कि शिक्षा,स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में है, क्योंकि एक सशक्त समाज ही एक सशक्त लोकतंत्र की नींव रख सकता है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक अवसर है,लेकिन यह अवसर तभी सार्थक होगा जब इसे ईमानदारी और दूरदर्शिता के साथ लागू किया जाएगा,अन्यथा यह भी एक नया मुखौटा बनकर रह जाएगा, जिसके पीछे वही पुरानी सत्ता की तस्वीर छिपी होगी।

गर्मी की मार,गिरता जनस्वास्थ्य : आखिर कब जागेगी नीति-व्यवस्था?

छाया भी लूट ली गई : देश चलाने वाले हाथ अब जल रहे हैं...
तपता भारत,टूटता स्वास्थ्य: क्या स्वास्थ्य आपातकाल की जरूरत नहीं?

प्रो.आर.के. जैन अरिजीत
बड़वानी,मध्यप्रदेश

तपता हुआ आसमान अब सिर्फ मौसम का मिज़ाज नहीं,बल्कि एक सुलगता संकट है जो हमारी सांसों,श्रम और अस्तित्व को चुपचाप निगल रहा है। आसमान की तीखी तपिश एक अदृश्य आपदा बन चुकी है, जिसने भारत में जीवन के संतुलन को डगमगा दिया है। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में गर्मी अब सहनशीलता की सीमा नहीं,बल्कि सीधे स्वास्थ्य पर प्रहार करने वाली ताकत बन गई है। बढ़ती हीटवेव की आवृत्ति और तीव्रता साफ दिखाती है कि यह अस्थायी नहीं,बल्कि स्थायी और गहराता संकट है। ऐसे में इसे केवल पर्यावरण का मुद्दा मानना भूल होगी; इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में स्वीकार करना अब न केवल आवश्यक, बल्कि अपरिहार्य हो गया है।

इस उभरते संकट की सबसे निर्मम मार उसी विशाल अनौपचारिक श्रमबल पर पड़ रही है, जो देश की अर्थव्यवस्था की धुरी है,फिर भी नीतिगत प्राथमिकताओं में हाशिये पर रहता है। भारत में अनौपचारिक क्षेत्र के करीब 12.8 करोड़ कार्यकर्ता–निर्माण स्थलों की धूल,सड़कों की तपिश,बाजारों की भीड़ और डिलीवरी के चक्र में जुटे मजदूर–खुले आसमान के नीचे बिना सुरक्षा के काम करने को विवश हैं। उन्हें न पर्याप्त छाया मिलती है, न स्वच्छ व ठंडे पानी की नियमित उपलब्धता, और न ही स्वास्थ्य सुरक्षा का भरोसेमंद तंत्र। यह विडंबना है कि जो हाथ देश की प्रगति को गति देते हैं,वही जलवायु संकट के सामने सबसे अधिक असहाय और असुरक्षित हैं।

स्वास्थ्य के मोर्चे पर बढ़ती गर्मी के दुष्प्रभाव अब गहरे,व्यापक और चिंताजनक रूप ले चुके हैं। ऊंचा तापमान हृदय संबंधी बीमारियों से होने वाली मौतों के खतरे को बढ़ा रहा है,वहीं गर्भवती महिलाओं में समय से पहले प्रसव का जोखिम 15-16 प्रतिशत तक बढ़ जाता है। निर्जलीकरण, अत्यधिक थकावट, गुर्दे की खराबी और मांसपेशियों में ऐंठन जैसे लक्षण अब अपवाद नहीं, बल्कि रोजमर्रा की सच्चाई

बनते जा रहे हैं। जो आंकड़े सामने आते हैं, वे इस संकट की केवल ऊपरी परत दिखाते हैं;असल तस्वीर कहीं अधिक भयावह है, जहां अनगिनत पीड़ाएं और मामले बिना दर्ज हुए चुपचाप दब जाते हैं।

गर्मी का प्रभाव अब केवल शरीर की सहनशक्ति तक सीमित नहीं रहा;यह बीमारियों की प्रकृति,उनकी गति और उनके फैलाव की दिशा तक को बदल रहा है। तापमान में निरंतर वृद्धि और वर्षा के अस्थिर पैटर्न ने मच्छरों के जीवनचक्र को इस तरह परिवर्तित किया है कि डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां तेजी से नए भूभागों,यहां तक कि हिमालयी क्षेत्रों में भी पैर पसार रही हैं। जो संक्रमण कभी सीमित भौगोलिक दायरों में बंधे थे,वे अब उन क्षेत्रों में भी उभर रहे हैं जहां पहले उनका नामोनिशान तक नहीं था। इस बदलाव ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर असामान्य दबाव डाल दिया है,जबकि पहले से ही वंचित और कमजोर समुदाय और अधिक खतरे में आ गए हैं। आर्थिक मोर्चे पर भी यह संकट अदृश्य चोट की तरह गहरा असर डाल रहा है। लैंसेट काउंटडाउन 2025 के अनुसार 2024 में गर्मी ने भारत से करीब 247 बिलियन श्रम घंटे छीन लिए,जिससे लगभग 194 बिलियन डॉलर की आय हानि हुई। 2030 तक गर्मी से 34 मिलियन पूर्णकालिक नौकरियां प्रभावित होने का अनुमान है। बढ़ती गर्मी ने श्रम उत्पादकता को इस हद तक प्रभावित किया है कि काम की रफ्तार धीमी पड़ रही है, जिससे मजदूरों की कमाई घट रही है और देश की आर्थिक प्रगति भी बाधित हो रही है। अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों की स्थिति सबसे अधिक दयनीय है, जहां बीमारी के दौरान विश्राम या आय-सुरक्षा जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती, इसलिए वे मजबूरी में काम जारी रखते हैं और अपनी सेहत को और गहरे संकट में धकेलते जाते हैं।

इसके बावजूद, नीति स्तर पर यह संकट अब भी अपेक्षित प्राथमिकता हासिल नहीं कर पाया है। हीटवेव को अभी राष्ट्रीय आपदा का दर्जा नहीं मिला है, जिसके कारण राहत,पुनर्वास और मुआवजे की व्यवस्था सीमित और धीमी बनी हुई है। नतीजतन, सबसे अधिक प्रभावित वर्ग ही सबसे कम संरक्षित रह जाता है। यदि जलवायु परिवर्तन को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया जाए, तो संसाधनों का अधिक प्रभावी और त्वरित आवंटन संभव होगा,निर्णय प्रक्रिया में तेजी आएगी और जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन मजबूत होगा। यह कदम औपचारिकता नहीं, बल्कि ठोस और निर्णायक बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित हो सकता है।

समाधान के स्तर पर अब आधे-अधूरे उपायों से आगे बढ़कर ठोस और व्यापक कार्रवाई की जरूरत है। अनौपचारिक मजदूरों के लिए हीट-सेफ्टी कानून लागू करना, हर कार्यस्थल पर छाया और स्वच्छ पानी की अनिवार्य उपलब्धता सुनिश्चित करना, तथा काम के घंटों को तापमान के अनुसार वैज्ञानिक ढंग से पुनर्निर्धारित करना बेहद जरूरी है। शहरी इलाकों में हरित क्षेत्र बढ़ाना, सुलभ कूलिंग सेंटर विकसित करना और जलवायु-लचीला स्वास्थ्य ढांचा तैयार करना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम होंगे। साथ ही, जागरूकता अभियानों को मजदूरों की भाषा, परिस्थितियों और जरूरतों के अनुरूप ढालना अनिवार्य है, ताकि ये उपाय वास्तव में प्रभावी बन सकें।

अब निर्णय की घड़ी आ चुकी है–यह मानने की कि जलवायु परिवर्तन कोई दूर का खतरा नहीं,बल्कि हमारे वर्तमान का सख्त और तेजी से विकराल होता सच है। इसकी तपिश अब केवल मौसम तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन,स्वास्थ्य और आजीविका के हर पहलू को झुलसा रही है। यदि इसे समय रहते सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में स्वीकार कर ठोस और साहसिक कदम नहीं उठाए गए,तो इसके परिणाम और अधिक भयावह और व्यापक होंगे। यह लड़ाई केवल पर्यावरण बचाने की नहीं,बल्कि मानव जीवन,सामाजिक न्याय और आर्थिक स्थिरता को सुरक्षित रखने की है–और अब इस सवाल को टालना,दरअसल, भविष्य को खतरे में डालना होगा।

इतिहास के पन्नों से बाहर निकलता अस्सी वर्ष का वह वीर कुंवर सिंह

डॉ. मुश्ताक़ अहमद शाह सहज़
हरदा,मध्य प्रदेश

इतिहास अक्सर तारीखों और आंकड़ों के बोझ तले दब जाता है,लेकिन कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनकी वीरता कालखंड की सीमाओं को तोड़कर वर्तमान के लिए मशाल बन जाती है। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह एक ऐसा ही नाम हैं। आज जब हम राष्ट्रवाद और साहस की नई परिभाषाएं गढ़ रहे हैं,तब जगदीशपुर के उस बूढ़े शेर का स्मरण केवल एक रस्म नहीं, बल्कि उस संकल्प को याद करना है जो उम्र की मोहताज नहीं होती।

कुंवर सिंह के व्यक्तित्व का सबसे विस्मयकारी पक्ष उनकी अवस्था थी। 80 वर्ष की आयु,जहाँ शरीर शिथिल होने लगता है,वहाँ कुंवर सिंह ने घोड़े की जीन पर बैठकर तलवार उठाई थी। यह केवल शारीरिक बल नहीं, बल्कि वह मानसिक दृढ़ता थी जिसे आज का युवा जज्बा कहता है। उनका जीवन इस मिथक को तोड़ता है कि क्रांति केवल युवाओं का विशेषाधिकार है। उन्होंने सिद्ध किया कि यदि ध्येय पवित्र हो और मातृभूमि के प्रति अनुराग गहरा हो, तो धमनियों में दौड़ता रक्त अस्सी की उम्र में भी उबाल मार सकता है।

रणकौशल और कूटनीति का संगम इस दृष्टि से देखें तो कुंवर सिंह का महत्व केवल उनके बलिदान तक सीमित नहीं है। वे एक विलक्षण सैन्य रणनीतिकार थे। सीमित संसाधनों के बावजूद, उन्होंने जिस तरह छापामार युद्ध का प्रयोग कर तत्कालीन विश्व की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति यानी ब्रिटिश हुकूमत को छकाया, वह आज भी सैन्य विशेषज्ञों के लिए शोध का विषय है। बिहार के जंगलों से लेकर आजमगढ़ के मैदानों तक, उनकी उपस्थिति अंग्रेजों के लिए एक अभेद्य पहेली बनी रही।

कुंवर सिंह का संघर्ष केवल सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं थी। वे एकता की मिसाल थे,उनकी सेना में हर जाति और धर्म के लोग शामिल थे। जुल्फिकार अली और रंगू बापू जैसे योद्धाओं के साथ उनका तालमेल यह दर्शाता है कि 1857 की नींव कितनी समावेशी थी। आज के खंडित समाज में कुंवर सिंह का नेतृत्व हमें याद दिलाता है कि जब लक्ष्य राष्ट्र की स्वतंत्रता हो, तो पहचान की तुच्छ दीवारें ढह जाती हैं।गंगा को अर्पित वह हाथ,समर्पण की पराकाष्ठा थी,

जब बलिया के पास शिवपुर घाट पर अंग्रेजी सेना की गोली उनके हाथ में लगी, तो उन्होंने विलाप करने या हार मानने के बजाय,अपनी तलवार से अपना ही हाथ

काटकर गंगा को भेंट कर दिया। यह घटना भारतीय इतिहास की सबसे साहसी और मार्मिक घटनाओं में से एक है। यह स्व के विसर्जन की वह पराकाष्ठा है,जो केवल एक ऋषि-तुल्य योद्धा ही कर सकता है।

वीर कुंवर सिंह आज केवल बिहार या जगदीशपुर के नहीं हैं,वे संपूर्ण भारत वर्ष की अदम्य जिजीविषा के प्रतीक हैं। उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि केवल उनकी प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करना नहीं, बल्कि उनके उस निर्भीक चरित्र को आत्मसात करना है। एक ऐसे समय में जब देश नई चुनौतियों से जूझ रहा है,वीर कुंवर सिंह का वह अजेय संकल्प हमें याद दिलाता है कि पराजय शरीर की नहीं,मन की होती है।

इतिहास गवाह है कि हाथ कटने के बाद भी जिस योद्धा ने विजय पताका फहराई हो, वह कभी मर नहीं सकता। वह विचारों में, लोकगीतों में और राष्ट्र की चेतना में सदैव जीवित रहता है।

वीर कुंवर सिंह,अदम्य साहस ,,,,
अस्सी वर्षो की देह कहां थकी थी,
तन मन में अंगारा था,
जगदीशपुर का वीर वह बूढ़ा ,
अंग्रेजों परपड़ा भारी था।
रजवाड़े सारे सोए थे जब,
महलों की आराम गाहों में,
इंकलाब की फ़िर गूँज उठी थी,
भोजपुर की तलवारों से।
हाथ कटा गया शीश झुक न पाया,
ये अद्भुत गौरव गाथा थी,
गंगा को सौंपी काट खुद भुजा
अपनी,ये उसकी मर्यादा थी।
सींचा जिसने रक्त बहाकर,
आज़ादी की इस फुलवारी को,
थर-थर कंपा दिया था जिसने,
गोरी सेना की मक्कारी को।
तलवार पुरानी म्यान से निकली,
बिजली बन कर गूंज उठी,
जो हिंदुस्तान की गली गली में,
ज्वाला बनकर धधक उठी।
उम्र अस्सी की रुकावट कहां बनी,
न ज़ख्मों ने रोक रस्ता,
विजय पताका लिए हाथों में,
वह लड़ा वीर बेपरवाह, चला।
नमन करो उस सेनानी को,
जिसने भारत का इतिहास रचा,
मरते दम तक वीर भूमि में वो कुंवर
शेरों की तरह डटा रहा।
जब तक गंगा मैया बहे धरा पर,
नाम कुंवर भी गूँजेगा,
वीर कुंवर का शौर्य सदा सदा ही,
भारत माँ को पूजेगा।

मन मिल जाए भोले में...

कार्तिकेय सीताराम त्रिपाठी
इन्दौर,मध्यप्रदेश

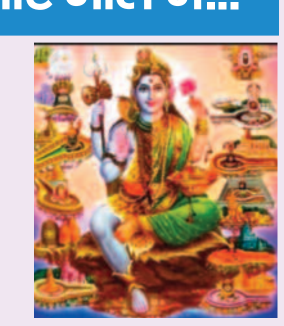

ये तन मिट्टी का है भोले,
आकर बस जाओ तुम भोले,
रीत अनोखी होगी भोले,
प्रीत में बंध जाओ तुम भोले।
ये तन मिट्टी ....
प्रेम की सीढ़ी सबसे ऊंची,
चढ़कर तुम आ जाओ भोले,
जीत सदा जीवन की होगी,
सत्य रूप में आओ भोले।
ये तन मिट्टी .....
जब-जब भाव शून्य होता मन,
भक्ति की अलख जलाओ भोले,
हम-तुम दोनों बस जाएं बस,
इतनी जगह बनाओ भोले।
ये तन मिट्टी ....
मद्धिम-मद्धिम पवन बह रही,
सुरभित तुम कर जाओ भोले,
तिनका-तिनका इस माटी का,
गीत तुम्हारे गाए भोले।
ये तन मिट्टी ......
आओ हम सब रच-बस जाएं,
भोले के इस मेले में,
धरा आसमां नाच उठे फिर,
मन मिल जाए भोले में।
ये तन मिट्टी ...
(262/320 वां मनका

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।
-सम्पादक

खमरिया में भाजपा की जिला संगोष्ठी,समरसता भोज से मजबूत हुआ सामाजिक एकता

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,19 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।

डॉ. अंबेडकर जयंती पखवाड़ा के तहत भाजपा मंडल देवगढ़ के ग्राम खम्हरिया में जिला स्तरीय संगोष्ठी सम्मेलन और समरसता भोज का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता, डॉ. भीमराव अंबेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्रों पर दीप प्रज्वलन और पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। मुख्य वक्ता वन विकास निगम के अध्यक्ष रामसेवक पैकरा और भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया सहित अन्य अतिथियों ने सम्मेलन को संबोधित किया। रामसेवक पैकरा ने अपने उद्बोधन में कहा कि बाबासाहेब अंबेडकर ने भारतीय समाज को समानता,स्वतंत्रता और बंधुत्व का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार अनुसूचित जाति-जनजाति वर्गों के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है और सामाजिक समरसता को मजबूत करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया ने कहा कि अंबेडकर के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और भाजपा उन्हें अपनी नीतियों में शामिल कर रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से 'शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो' के संदेश को गांव-गांव तक पहुंचाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में रामलखन सिंह पैकरा, संयोजक मधुसूदन शुक्ला, जिला पंचायत सदस्य राधा रवि और मंडल अध्यक्ष अखंड विधायक सिंह ने भी अपने विचार रखे। मंच संचालन जिला महामंत्री विनोद हर्ष ने किया, जबकि आभार प्रदर्शन प्रबोध सिंह ने किया। इस अवसर पर अनुसूचित जाति समाज के 10 वरिष्ठ महिला-पुरुषों का शाल-श्रीफल देकर सम्मान किया गया।

फ्लाईओवर की मांग के बीच शहर की अव्यवस्था पर घमासान

भाजपा नेता कैलाश मिश्रा के कटाक्ष के बाद कई आवाजें उठीं

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,19 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।

शहर की यातायात व्यवस्था, अतिक्रमण और सड़क किनारे लगने वाले ठेलों को लेकर अब राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा नेता एवं समाजसेवी कैलाश मिश्रा द्वारा आकाशवाणी चौक से संतोष किराना तक फ्लाईओवर बनाने की मांग और चौपाटी क्षेत्र की अव्यवस्था पर कटाक्ष करने के बाद कई अन्य लोगों ने भी नगर निगम व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। कैलाश मिश्रा ने कहा था, 'महापौर जी आकाशवाणी चौक से संतोष किराना तक फ्लाईओवर बनवा दीजिए,चौपाटी में सड़क पर ठेले लगते हैं तो फिर लोग आएं-जाएं कैसे?' उनके इस बयान के बाद शहर में ट्रैफिक व्यवस्था और अतिक्रमण को लेकर चर्चा तेज हो गई। इसी क्रम में राजेश पांडेय 'अब्र' ने कहा कि न चौपाटी की अव्यवस्था में कमी आई,न सिविल कोर्ट के सामने की समस्या खत्म हुई और न ही स्कूल रोड के ठेलेवाले सुधरे। उन्होंने कहा कि जब भी नगर निगम कर्मचारी व्यवस्था सुधारने जाते हैं,दूसरे या तीसरे दिन फिर वही स्थिति बन जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन तीनों स्थानों पर ठेले वाले सड़क पर चढ़ाकर दुकानें लगाते हैं और ग्राहक पूरी सड़क घेरकर खड़े रहते हैं, जिससे आवागमन बाधित होता है। कई बार इसी वजह से बेवजह झगड़े की स्थिति भी बनती है। वहीं असीम सेन गुप्ता ने कहा कि आकाशवाणी चौक शहर का सबसे बदहाल क्षेत्र बन चुका है। अब आधी सड़क पर दुकानें लगने लगी हैं। उन्होंने कहा कि इच्छाशक्ति के अभाव में ऐसी अव्यवस्थाएं जन्म लेती हैं। बगल में सुरक्षित बाजार बना हुआ है, जहां शेड और चबूतरा भी है, लेकिन उसे आबाद करने की दिशा में कोई गंभीर प्रयास नहीं हो रहा। इधर कांग्रेसी पार्षद शुभम जायसवाल ने भी निगम व्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए कहा कि नगर निगम के अधिकारी काम करने को तैयार हैं,लेकिन वहां बैठे नेता उन्हें अच्छे से काम नहीं करने देते। यदि अधिकारियों को स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाए तो शहर का नक्शा ही बदल सकता है। बताया जा रहा है कि हाल ही में नगर निगम आयुक्त ने चौपाटी क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए ठेलों को हटवाया था। इस दौरान दो से तीन दिनों तक जेसीबी और ट्रैक्टर लगाए गए, जिससे निगम का खर्च भी हुआ। हालांकि कुछ दिनों बाद फिर उसी स्थान पर ठेले लगने लगे। शहरवासियों का कहना है कि केवल अस्थायी कार्रवाई से समस्या का समाधान नहीं होगा। स्थायी योजना, वैकल्पिक बाजार स्थल, पार्किंग व्यवस्था और सख्त निगरानी के बिना शहर को जाम और अव्यवस्था से राहत मिलना मुश्किल है।

स्वरंग किड्स एकेडमी पर कार्रवाई को लेकर विवाद गहराया,सामाजिक कार्यकर्ता ने उठाए सवाल

शहर के चोपड़ापारा स्थित स्वरंग किड्स एकेडमी के विरुद्ध स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश मिश्रा ने विभागीय कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे एकतरफा और दबाव में लिया गया निर्णय बताया है। कैलाश मिश्रा ने कहा कि स्कूल प्रबंधन द्वारा 5 जून 2025 को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में विधिवत आवेदन प्रस्तुत कर स्कूल संचालन की जानकारी देने के साथ मान्यता संबंधी मार्गदर्शन मांगा गया था। इसके बावजूद विभाग ने करीब 10 महीनों तक आवेदन पर कोई पहल नहीं की। ऐसे में अचानक स्कूल संचालन स्थगित करने और एक लाख रुपए अर्थदंड लगाने का आदेश जारी करना समझ से परे है। उन्होंने आरोप लगाया कि जारी आदेश में स्कूल प्रबंधन द्वारा अपनी गलती स्वीकार करने का उल्लेख किया गया है, जबकि जांच प्रतिवेदन में ऐसी कोई स्वीकारोक्ति नहीं है। मिश्रा के अनुसार जांच रिपोर्ट में स्कूल की अधोसंरचना, मानव संसाधन और बच्चों की देखभाल से जुड़ी व्यवस्थाओं को संतोषजनक एवं बेहतर बताया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब व्यवस्थाएं उचित पाई गई,तो फिर कठोर कार्रवाई किस आधार पर की गई। साथ ही दावा किया कि यह कार्रवाई कलेक्टर के अनुमोदन के बिना की गई है, जिससे पूरी प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न खड़ा होता है।

डे-केयर सेंटर बंद होने से अभिभावक परेशान: कैलाश मिश्रा ने कहा कि संबंधित संस्थान केवल स्कूल ही नहीं, बल्कि डे-केयर सेंटर के रूप में भी संचालित था, जहां कामकाजी अभिभावक अपने बच्चों को सुरक्षित माहौल में छोड़कर निश्चिंत होकर कार्य पर जाते थे। अचानक कार्रवाई के बाद ऐसे अभिभावकों के सामने बच्चों की देखभाल की नई समस्या खड़ी हो गई है।

निष्पक्ष जांच की मांग: उन्होंने पूरे मामले में पारदर्शिता लाने, कार्रवाई पर पुनर्विचार करने तथा जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की एकतरफा कार्रवाई दोबारा न हो।

परंपरा के उलट अनोखी शादी : दुल्हन बारात लेकर पहुंची,दूल्हे की हुई विदाई

सरगुजा के सुलपगा गांव में 'मसी' परंपरा के तहत हुआ विवाह, घर जमाई बना दूल्हा

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,19 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के ग्रामीण क्षेत्र सुलपगा गांव में एक अनोखी शादी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। यहां पारंपरिक रीति-रिवाजों से हटकर दुल्हन खुद बारात लेकर दूल्हे के घर पहुंची और 'मसी' परंपरा के तहत विवाह संपन्न हुआ। शादी में सबसे खास बात यह रही कि दुल्हन की जगह दूल्हे की विदाई हुई, जो लोगों के लिए कौतूहल का विषय बन गया। दुल्हन देवमुनि एक्का के पिता मोहन एक्का ने बताया कि उनके परिवार में चार बेटियां हैं और कोई बेटा नहीं है। ऐसे में परिवार के सहारे के लिए उन्होंने यह निर्णय लिया। उन्होंने खुद बारात लेकर दूल्हे बिलासुस बरवा के घर पहुंचकर विवाह की रस्में पूरी कीं। इस विवाह में परंपरागत 'कन्यादान' की जगह 'वरदान' की रस्म निभाई गई। शादी पूरी तरह स्थानीय रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न हुई और दहेज जैसी प्रथा से दूरी रखी गई।

दूल्हे की विदाई ने खींचा ध्यान : शादी के बाद दूल्हे की विदाई की गई, जो आमतौर पर दुल्हन की होती है। विदाई के दौरान दूल्हा भावुक होकर रो पड़ा। यह दृश्य वहां मौजूद लोगों के लिए नया और भावनात्मक अनुभव रहा।

घर जमाई बनेगा दूल्हा

मोहन एक्का ने बताया कि दूल्हे को वे अपने घर ले जाकर बेटे की तरह रखेंगे। यह फैसला परिवार की जरूरत को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

'चुमान' परंपरा का भी पालन

बारात में शामिल महेश तिर्की ने बताया कि उनके समाज में 'चुमान' नामक परंपरा होती है, जिसमें शादी के बाद लडक़े पक्ष की ओर से दहेज दिया जाता है।

पहली बार देखा ऐसा विवाह

लडक़े पक्ष की उर्मिला बरवा ने कहा कि यह उनके लिए पहली बार का अनुभव है, जब लडक़ी पक्ष बारात लेकर आया और दूल्हा घर जमाई बना।

समाज में चर्चा का विषय

इस अनोखी शादी ने क्षेत्र में नई सोच और परंपराओं में बदलाव को लेकर चर्चा शुरू कर दी है। लोग इसे सामाजिक जरूरत के अनुसार लिया गया सकारात्मक कदम मान रहे हैं।

लू के आसार : सरगुजा में तापमान 41 डिग्री,बढ़ती गर्मी ने बढ़ाई चिंता

आने वाले दिनों में और बढ़ेगा पारा,डॉक्टरों ने जारी की सावधानी की सलाह

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,19 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।

उत्तर छत्तीसगढ़ में तेज गर्मी अब चिंता का कारण बनती जा रही है। राजस्थान की ओर से आ रही गर्म हवाओं के चलते सरगुजा संभाग में तापमान लगातार बढ़ रहा है। रविवार को अंबिकापुर में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम 23.4 डिग्री रहा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है,जिससे लू चलने की स्थिति बन सकती है। शहर में सुबह 10 बजे के बाद ही धूप तीखी हो जाती है। दोपहर में हालात इतने खराब हो जाते हैं कि लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। शनिवार को जहां अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री था,वहीं एक दिन में ही यह 41 डिग्री तक पहुंच गया। कूलर और पंखे भी गर्मी से राहत देने में नाकाम साबित हो रहे हैं। भीषण गर्मी के कारण बाजार में ठंडे पेय और फलों की मांग बढ़ गई है। तरबूज,खीरा,ककड़ी,लस्सी और गन्ना जूस की बिक्री में तेजी देखी जा रही है। लोग शरीर को ठंडा रखने के लिए अधिक से अधिक तरल पदार्थों का सेवन कर रहे हैं।

स्वास्थ्य पर पड़ रहा असर,अलर्ट जारी : गर्मी का असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पडने लगा है। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि दोपहर के समय अनावश्यक बाहर न निकलें। जरूरी काम सुबह या शाम को ही करें और दिनभर पर्याप्त पानी पीते रहें।

चेहरा ढंककर निकल रहे लोग : धूप से बचने के लिए लोग गमछा, तौलिया और स्कार्फ का इस्तेमाल कर रहे हैं। सडक़ पर निकलते समय अधिकतर लोग चेहरा ढंककर ही बाहर जा रहे हैं।

मौसम वैज्ञानिक की चेतावनी : मौसम वैज्ञानिक एस.के. मंडल के अनुसार, अगर तापमान में 2 डिग्री की और बढ़ोतरी होती है, तो क्षेत्र में लू चलने लगेगी।

पवन तिवारी आत्महत्या केस की जांच पर उठा सवाल,राजेश सिंह सिसोदिया ने आईजी से की निष्पक्ष विवेचना की मांग

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,19 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।

शहर के चर्चित पवन तिवारी आत्महत्या प्रकरण में एक बार फिर पुलिस विवेचना को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। मामले में सामाजिक कार्यकर्ता राजेश सिंह सिसोदिया ने सरगुजा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) को ज्ञापन सौंपते हुए अंबिकापुर कोतवाली पुलिस की जांच प्रक्रिया में गंभीर कमियों का आरोप लगाया है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष एवं तथ्यात्मक पुनः समीक्षा कराने की मांग की है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि अंबिकापुर निवासी श्री आदित्य नारायण तिवारी के स्वर्गीय पुत्र पवन तिवारी द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले में थाना कोतवाली,जिला सरगुजा में अपराध क्रमांक 915/2025,दिनांक 06 दिसंबर 2025 को दर्ज किया गया था। इसके बाद पुलिस द्वारा मामले की विवेचना की जा रही है,लेकिन अब तक की जांच में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं की अनदेखी किए जाने का आरोप लगाया गया है। राजेश सिंह सिसोदिया ने ज्ञापन में कहा है कि केस डायरी में आत्महत्या से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों,परिस्थितियों तथा घटना से संबंधित वीडियो साक्ष्यों का समुचित उल्लेख नहीं किया गया है। उनका कहना है कि यदि उपलब्ध साक्ष्यों को रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया गया,तो न्यायालय में मामला कमजोर हो सकता है,जिससे पीड़ित परिवार को न्याय मिलने में कठिनाई होगी। उन्होंने आईजी से मांग की है कि पूरे मामले की उच्चस्तरीय समीक्षा कराई जाए तथा विवेचना अधिकारी को निर्देशित किया जाए कि सभी इलेक्ट्रॉनिक,दस्तावेजी एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को केस डायरी में शामिल किया जाए। साथ ही जांच निष्पक्ष,पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए। राजेश सिंह सिसोदिया ने कहा कि किसी भी संवेदनशील प्रकरण में जांच की छोटी सी चूक भी न्याय प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। इसलिए पवन तिवारी आत्महत्या मामले में हर पहलू की गंभीरता से जांच होना जरूरी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि पुलिस प्रशासन मामले को गंभीरता से लेते हुए उचित कार्रवाई करेगा।

सामाजिक एकता का संदेश बनी परशुराम जयंती..शहरभर में दिखा उत्साह

शोभायात्रा में उमड़ा जनसैलाब,महिलाओं की सहभागिता रही खास आकर्षण

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,19 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा में रविवार को मनाई गई भगवान परशुराम जयंती इस बार सिर्फ धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं रही, बल्कि सामाजिक एकता और सहभागिता का बड़ा संदेश भी दे गई। सर्व ब्राह्मण समाज के तत्वावधान में हुए कार्यक्रमों में शहरभर के लोगों ने बढ़-चढक़र हिस्सा लिया। शाम को गांधी चौक स्थित दुर्गा मंदिर से निकली भव्य शोभायात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं एक समान परिधान में शामिल हुईं। भगवान परशुराम की जीवंत झांकी के साथ चल रही महिलाओं की अनुशासित उपस्थिति आयोजन का प्रमुख आकर्षण रही। शोभायात्रा गांधी चौक से निकलकर घड़ी चौक, देवीगंज रोड, संगम चौक, महामाया चौक और स्कूल रोड होते हुए लरंगसाय चौक पहुंची। इसके बाद केनाबांध स्थित परशुराम मंदिर प्रांगण में समापन हुआ, जहां पूजा-अर्चना और महाआरती की गई।

दिनभर चले धार्मिक अनुष्ठान : सुबह केनाबांध मंदिर में भगवान परशुराम का पंचामृत अभिषेक, पूजा-अर्चना और आरती की गई। साथ ही 24 घंटे का अखंड रामायण पाठ भी आयोजित हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने भाग लिया।

जगह-जगह हुआ स्वागत : शोभायात्रा के दौरान विभिन्न समाज और संगठनों द्वारा जगह-जगह स्वागत किया गया। लोगों ने पुष्पवर्षा कर श्रद्धा व्यक्त की।

बड़ी संख्या में लोग रहे मौजूद : कार्यक्रम में समाज के पदाधिकारी और सदस्य बड़ी संख्या में शामिल हुए। आयोजन ने शहर में धार्मिक उत्साह के साथ सामाजिक एकजुटता का माहौल भी बनाया।

'गीता का ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं,जीवन में अपनाने के लिए'

ब्रह्माकुमारी संस्था में सात दिवसीय कार्यक्रम का समापन,राजयोग शिविर आज से...

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,19 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।

ब्रह्माकुमारी संस्था द्वारा आयोजित श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान कार्यक्रम के सातवें दिन गीता के संदेशों के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय परंपरा अनुसार दीप प्रज्वलन और देव पूजन से की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में नगर निगम महापौर मंजूषा भगत एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष फुलेश्वरी सिंह उपस्थित रहीं। अतिथियों ने मुख्य वक्ता सिवनी (मध्यप्रदेश) से आई योग शक्ति गीता दीदी का शाल, श्रीफल और पुष्पगुच्छ से सम्मान किया। गीता दीदी ने अपने संबोधन में कहा कि गीता का ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में अपनाने के लिए है। उन्होंने कहा कि 'आंसू बहाने से नहीं, बल्कि एकाग्रता और श्रेष्ठ कर्म से भाग्य बदलता है।' हर व्यक्ति के अंदर राम और रावण दोनों प्रवृत्तियां होती हैं, इसलिए आवश्यक है कि हम अपने भीतर के अच्छे गुणों को विकसित करें और नकारात्मकता को समाप्त करें। कार्यक्रम के अंतिम दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर अपने अंदर की बुराइयों और नकारात्मक संस्कारों को त्यागने का संकल्प लिया।

आज से शुरू होगा राजयोग शिविर : संस्था द्वारा 19 अप्रैल से राजयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सुबह 6 बजे म्यूजिकल एक्सरसाइज, 7 से 8 बजे तक राजयोग मेडिटेशन तथा शाम 6 से 7 बजे तक प्रतिदिन सत्र आयोजित होंगे। आयोजकों ने अधिक से अधिक लोगों से शिविर में भाग लेने की अपील की है।

हाईकोर्ट की टिप्पणी बेअसर? कोरिया में प्रभारी सीईओ चला रहे व्यवस्था

जनपद सीईओ प्रभार विवाद...हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी क्यों जारी 'प्रभारी राज'?

- नियुक्त सीईओ बाहर,प्रभारी अंदर–कोरिया में प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल
- आदेश शासन का...नियंत्रण कहीं और–जनपद सीईओ प्रभार पर उठे गंभीर सवाल
- प्रभार के पीछे क्या है खेल? जनपद सीईओ हटाने पर लेनदेन की चर्चा तेज
- जनपद सीईओ विवाद में अधिकार छिने...प्रभारी बने साहब–व्यवस्था कटघरे में...
- कोरिया में उल्टी व्यवस्था की कहानी नियुक्त सीईओ बैठे खाली...प्रभारी चला रहे काम...
- नियमों से ऊपर 'प्रभारी व्यवस्था'? हाईकोर्ट निर्देश के बाद भी नहीं बदली तस्वीर

-रवि सिंह-
कोरिया,19 अप्रैल 2026
(घटती-घटना)।
जनपद पंचायतों में सीईओ के प्रभार को लेकर कोरिया जिले में एक ऐसा प्रशासनिक विवाद सामने आया है,जिसने व्यवस्था की पारदर्शिता,अधिकारों की वैधता और निर्णय प्रक्रिया की निष्पक्षता पर कई गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं, शासन द्वारा विधिवत नियुक्त जनपद सीईओ को उनके पद से अलग कर अन्य अधिकारियों को 'प्रभारी सीईओ' के रूप में काम सौंपा जाना अब केवल एक प्रशासनिक व्यवस्था का मामला नहीं रह गया है,बल्कि यह संभावित अनियमितताओं और लेनदेन की आशंकाओं से भी जुड़ता जा रहा है,सबसे अहम बात यह है कि उच्च न्यायालय की स्पष्ट टिप्पणी के बावजूद भी कई स्थानों पर स्थिति में कोई बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है,जिससे पूरे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है।

हाईकोर्ट की टिप्पणी के बावजूद स्थिति जस की तस

जनपद सीईओ प्रभार विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उच्च न्यायालय की वह टिप्पणी है, जिसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि शासन द्वारा नियुक्त जनपद सीईओ को कलेक्टर किसी भी परिस्थिति में उनके प्रभार से नहीं हटा सकते। यह अधिकार केवल शासन के पास सुरक्षित है,गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में इसी तरह के एक मामले में हटाई गई सीईओ द्वारा न्यायालय का दरवाजा खटखटाने पर यह स्पष्ट निर्देश सामने आया था,इस निर्णय को प्रशासनिक व्यवस्था में एक मार्गदर्शक के रूप में देखा गया, इसके बावजूद कोरिया जिले में इस आदेश का पालन होते नहीं दिख रहा है। यहां दो विकासखंडों में अब भी प्रभारी सीईओ ही कार्यभार संभाले हुए हैं, जबकि शासन से नियुक्त वास्तविक सीईओ कार्यालयों में निष्क्रिय बैठे हैं,यह स्थिति न केवल न्यायालय के आदेश की अवहेलना का संकेत देती है, बल्कि प्रशासनिक इच्छाशक्ति पर भी सवाल खड़ा करती है।

दो विकासखंडों में समान स्थिति-

कोरिया जिले के दोनों विकासखंडों में एक जैसी स्थिति सामने आई है, दोनों ही स्थानों पर शासन द्वारा नियुक्त जनपद सीईओ को उनके कार्य से अलग कर दिया गया है और उनकी जगह अन्य अधिकारियों को प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी दे दी गई है, इस व्यवस्था के चलते वास्तविक सीईओ कार्यालय में मौजूद तो हैं, लेकिन उन्हें कोई प्रभावी कार्य नहीं दिया जा रहा, वे केवल औपचारिक उपस्थिति तक सीमित होकर रह गए हैं, यह स्थिति प्रशासनिक दृष्टि से असामान्य है, क्योंकि किसी पद पर नियुक्त अधिकारी को अधिकार से वंचित करना न केवल नियमों के विरुद्ध है, बल्कि यह कार्य प्रणाली को भी प्रभावित करता है।

नियुक्त सीईओ का मनोबल प्रभावित–शासन द्वारा हाल ही में पदोन्नति के माध्यम से कई अधिकारियों को जनपद सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया था,इन अधिकारियों को नई जिम्मेदारी के साथ कार्य करने का अवसर मिला था,लेकिन वर्तमान स्थिति में उन्हें अपने अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है,कोरिया जिले में ऐसे कई युवा अधिकारी हैं, जो इस स्थिति से मानसिक रूप से प्रभावित हो रहे हैं,उन्हें कार्य का अवसर नहीं मिल रहा,उनके निर्णय लेने के अधिकार सीमित कर दिए गए हैं और वे केवल औपचारिक भूमिका में सिमट गए हैं,इसका सीधा असर उनके आत्मविश्वास और कार्यक्षमता पर पड़ता है,जो लंबे समय में प्रशासनिक गुणवत्ता को भी प्रभावित कर सकता है।

पुराने प्रभारी अधिकारियों की भूमिका

इस पूरे विवाद के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण लंबे समय से प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे अधिकारियों की भूमिका भी मानी जा रही है,जब शासन ने पदोन्नति के माध्यम से नए सीईओ की नियुक्ति की,तब पहले से प्रभारी के रूप में काम कर रहे अधिकारियों को अपने पद से हटना पड़ा, इससे उनमें असंतोष की स्थिति उत्पन्न हुई, सूत्रों के अनुसार, इन अधिकारियों ने अपने स्थानीय प्रभाव और अनुभव का उपयोग करते हुए नए सीईओ के लिए कार्य करना कठिन बना दिया,स्थानीय नेटवर्क का इस्तेमाल,प्रशासनिक प्रक्रियाओं में बाधाएं और कार्य निष्पादन में सहयोग की कमी इन सब कारणों से नए सीईओ को अपने दायित्व निभाने में कठिनाई हुई,जिसका परिणाम यह हुआ कि कुछ स्थानों पर पुनः प्रभारी व्यवस्था प्रभावी हो गई।

प्रभार देने की प्रक्रिया पर सवाल

प्रभारी सीईओ नियुक्त किए जाने की प्रक्रिया भी सवालों के घेरे में है, क्या यह निर्णय नियमों के अनुरूप लिया गया? क्या इसके लिए शासन की अनुमति ली गई? या यह स्थानीय स्तर पर लिया गया निर्णय है? इन सवालों के स्पष्ट जवाब सामने नहीं आ रहे हैं, जिससे संदेह की स्थिति और गहरी हो रही है।

लेनदेन की चर्चाएं और बढ़ता संदेह

इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे संवेदनशील मुद्दा संभावित लेनदेन का है,हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन लगातार उठ रही चर्चाएं इस दिशा में इशारा करती हैं कि प्रभारी बनाए जाने के पीछे आर्थिक या अन्य प्रकार के प्रभाव की भूमिका हो सकती है,जब नियुक्त अधिकारी निष्क्रिय हों और प्रभारी अधिकारी सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हों,तो यह स्थिति स्वाभाविक रूप से संदेह पैदा करती है,यह जरूरी है कि इन चर्चाओं की सत्यता की निष्पक्ष जांच हो,ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके।

प्रशासनिक व्यवस्था पर व्यापक असर

इस तरह की स्थिति का असर केवल अधिकारियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह पूरे प्रशासनिक ढांचे को प्रभावित करता है, योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी निर्णय प्रक्रिया में भ्रम और जवाबदेही की कमी जब अधिकार और जिम्मेदारी अलग-अलग लोगों के पास होती है, तो कार्य में समन्वय की कमी आना स्वाभाविक है, इसका सीधा असर आम जनता तक पहुंचने वाली सेवाओं पर पड़ता है।

न्यायालय के आदेश का पालन जरूरी

उच्च न्यायालय के आदेश केवल एक मामले तक सीमित नहीं होते, बल्कि वे प्रशासनिक व्यवस्था के लिए मार्गदर्शक होते हैं, ऐसे में यह आवश्यक है कि न्यायालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए,नियुक्त अधिकारियों को उनका अधिकार वापस दिया जाए और यदि किसी स्तर पर अनियमितता है, तो उसकी जांच कर कार्रवाई की जाए।

स्पष्टता और पारदर्शिता की जरूरत

जनपद सीईओ प्रभार विवाद अब एक गंभीर प्रशासनिक मुद्दा बन चुका है,जिसमें पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है,जरूरत इस बात की है कि स्थिति को स्पष्ट किया जाए,सभी संबंधित पक्षों की भूमिका की जांच हो और नियमों के अनुसार निर्णय लिए जाएं जब तक यह स्पष्ट नहीं होता कि प्रभार किस आधार पर दिया गया है,तब तक यह सवाल बना रहेगा 'क्या यह केवल प्रशासनिक निर्णय है,या इसके पीछे कोई और कारण छिपा हुआ है? '

शादी का झांसा देकर नाबालिग को जम्मू ले गया,दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

-संवाददाता-
सरगुजा,19 अप्रैल 2026
(घटती-घटना)।
थाना मणीपुर पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को जम्मू से गिरफ्तार किया है। आरोपी नाबालिग को बहला-फुसलाकर शादी का झांसा देकर अपने साथ जम्मू ले गया था। पुलिस ने पीड़िता को सुरक्षित बरामद कर लिया है।झ पुलिस के मुताबिक, 9 अप्रैल 2026 को पीड़िता की मां ने थाना मणीपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी 24 जनवरी 2026 से किराये के कमरे से बिना बताए लापता है। परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि नाबालिग जम्मू के विजयपुर इलाके में आरोपी अजय शंकर तिवारी के साथ है। इस पर पुलिस टीम को तत्काल जम्मू रवाना किया गया। टीम ने वहां दबिश देकर नाबालिग को बरामद किया और आरोपी को हिरासत में लिया। पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसे बहला-फुसलाकर जम्मू ले गया और शादी का झांसा देकर जबरन दुष्कर्म किया। आरोपी की पहचान अजय शंकर तिवारी (26), निवासी डोरला, थाना बलौदा, जिला जांजगीर-चांपा के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 64(2)(ड़) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 के तहत कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया है।

पुलिस टीम की रही अहम भूमिका : इस कार्रवाई में थाना प्रभारी उप निरीक्षक सीपी तिवारी, एएसआई अनिल पाण्डेय, प्रधान आरक्षक अंजू एक्का, आरक्षक सत्येंद्र दुबे।

अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर सोशल मीडिया में घमासान,टिप्पणियों से गरमाई सियासत...

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,19 अप्रैल 2026
(घटती-घटना)।
शहर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई और नगर निगम की कार्यशैली को लेकर सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। एक पोस्ट पर आई टिप्पणियों ने शहर की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है। सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट में लिखा गया कि 'जितना जल्दी पाटना है पाट दीजिए,आज टीम नहीं जाएगी। कहने वाले और रोकने वाले कौन हैं,क्या जानते हैं?' इसके बाद पोस्ट पर कई लोगों ने अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दी। गोपाल पांडेय ने टिप्पणी करते हुए लिखा कि '...खोर और क्या,लेकिन वह कौन है नाम भी आना चाहिए।' वहीं नितिन चौहान ने सवाल उठाते हुए कहा कि लोगों के बीच चर्चा है कि किसी व्यक्ति ने इस कार्रवाई को रुकवाने की जिम्मेदारी ली है,क्या यह सही है? विश्वनाथ गुप्ता ने टिप्पणी में कहा कि पाटने वाले अतिक्रमणकारी हैं और टीम कहने वाले जनप्रतिनिधि। उन्होंने कटाक्ष करते हुए लिखा कि 'जो नहीं खाता,वह बोलता है और जो खाता है, वह सबकी सुनता है। 'इसी बीच धनंजय मिश्रा ने लिखा कि 'आपको तो सभी का नाम पता है, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप नाम सार्वजनिक करें। 'शहर में लगातार चल रही अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई के बीच इन टिप्पणियों ने यह संकेत दिया है कि नगर निगम की कार्रवाई को लेकर आम लोगों में असंतोष और सवाल दोनों मौजूद हैं। कुछ लोग इसे प्रभावी कार्रवाई मान रहे हैं,तो कुछ का आरोप है कि दबाव और हस्तक्षेप के कारण अभियान अधूरा रह जाता है। गौरतलब है कि चौपाटी,आकाशवाणी चौक,स्कूल रोड और अन्य क्षेत्रों में सड़क किनारे ठेले और अस्थायी दुकानें लगाए जाने से यातायात प्रभावित होता रहा है। निगम द्वारा समय-समय पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही स्थिति बनने लगती है। सोशल मीडिया पर उठी इस बहस के बाद शहर में अब यह चर्चा तेज है कि आखिर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में रुकावट कौन डाल रहा है और प्रशासन कब तक स्थायी समाधान निकाल पाएगा।

प्रधानमंत्री आवास को मनरेगा मजदूरी भुगतान,मुख्यमंत्री आवास हितग्राहियों को अब तक नहीं मिली 23 हजार की राशि

-संवाददाता-
राजपुर,19 अप्रैल 2026
(घटती-घटना)।
जिले के राजपुर जनपद क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के बीच भुगतान को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को मनरेगा मजदूरी की राशि का भुगतान किया जा रहा है, वहीं मुख्यमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को मिलने वाली 23 हजार रुपए मजदूरी राशि अब तक नहीं मिली है। इससे लाभार्थियों में नाराजगी और मायूसी देखी जा रही है। जानकारी के अनुसार, वर्ष 2023 विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने आर्थिक सर्वे कराकर जरूरतमंद परिवारों के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू की थी। चयनित हितग्राहियों के खातों में पहली किस्त के रूप में 25-25 हजार रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए थे। बाद में प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद योजना जारी रही और दूसरी व तीसरी किस्त भी कई हितग्राहियों को दी गई।

राजपुर क्षेत्र में 32 हितग्राही चयनित : राजपुर जनपद क्षेत्र में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत कुल 32 हितग्राही चयनित किए गए थे। इनमें कई लाभार्थियों ने मकान निर्माण का कार्य टॉप लेवल और सेंटरिंग ढलाई तक पूरा करा लिया है। बावजूद इसके, निर्माण कार्य में मिलने वाली मनरेगा मजदूरी की राशि अब तक जारी नहीं की गई है।

दोहरा मापदंड क्यों? ग्रामीणों का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में मनरेगा मजदूरी का लाभ दिया जा रहा है, तो मुख्यमंत्री आवास योजना में यह सुविधा क्यों नहीं दी जा रही? हितग्राहियों का आरोप है कि मजदूरी भुगतान नहीं होने से उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है।

अधिकारियों ने क्या कहा : जनपद पंचायत में पदस्थ आवास विभाग के अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत चयनित हितग्राहियों की औपचारिकताएं पूरी कर जिला कार्यालय भेज दी गई हैं। मजदूरी भुगतान शासन स्तर से होना है। वहीं जनपद पंचायत राजपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संजय दुबे ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मनरेगा मजदूरी की 23 हजार रुपए राशि अभी तक शासन से प्राप्त नहीं हुई है।

छात्रसंघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर एनएसयूआई ने सौंपा ज्ञापन

-संवाददाता-
राजपुर,19 अप्रैल 2026
(घटती-घटना)।
भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के प्रदेशव्यापी चरणबद्ध आंदोलन के तहत छात्रसंघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर एनएसयूआई नेताओं ने सामरी विधायक के नाम ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन छात्र नेता आदित्य विभु जायसवाल के नेतृत्व में विधायक प्रतिनिधि प्रवीण अग्रवाल को सौंपा गया। एनएसयूआई नेता आदित्य विभु जायसवाल ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में छात्रसंघ चुनाव की बहाली की मांग को लेकर आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय एनएसयूआई के उपाध्यक्ष आदित्य विभु जायसवाल के नेतृत्व में यह ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई है कि प्रदेश के सभी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव तत्काल कराया जाए। ज्ञापन में कहा गया कि पिछले कई वर्षों से छात्रसंघ चुनाव नहीं होने के कारण छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है और उनकी समस्याएं प्रशासन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। एनएसयूआई ने मांग की है कि छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए शीघ्र चुनाव कार्यक्रम घोषित कर पारदर्शी तरीके से चुनाव कराया जाए।

बैगा जनजाति की बेटी से छिना हक?

महिला बाल विकास विभाग पर गंभीर आरोप

राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र समुदाय की बेटी न्याय को तरसी...भर्ती प्रक्रिया कटघरे में...

पात्रता के बावजूद बाहर,नियुक्ति में गड़बड़ी के आरोप—बैगा युवती भटकने को मजबूर

जनदर्शन में शिकायत,फिर भी कार्रवाई नहीं...आंगनबाड़ी भर्ती पर सवाल...

स्थानीय को दरकिनार,बाहरी को नियुक्ति? चेरवापारा भर्ती विवाद गहराया...

नियम ताक पर...नियुक्ति जारी...आंगनबाड़ी सहायिका चयन पर विवाद

तीन महीने बाद भी जांच नहीं,बैगा युवती न्याय के इंतजार में...

कागजों में न्याय,जमीनी हकीकत अलग...आंगनबाड़ी भर्ती पर उठे गंभीर प्रश्न...

-राजेन्द्र शर्मा-

खड़गवां,19 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)। जिले के महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र चेरवापारा,शंकरगढ़ में सहायिका पद पर हुई नियुक्ति अब गंभीर सवालों के घेरे में आ गई है,विशेष पिछड़ी बैगा जनजाति (राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र समुदाय) की एक युवती ने आरोप लगाया है कि उसने सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ नियमानुसार आवेदन किया था,वह केंद्र क्षेत्र की मूल निवासी होने के साथ पात्रता सूची में प्राथमिकता की हकदार थी,इसके बावजूद उसे सूची से बाहर कर दिया गया। बता दे की जिले में आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती को लेकर सामने आया यह मामला अब केवल एक नियुक्ति विवाद नहीं रह गया है,बल्कि यह प्रशासनिक संवेदनशीलता,नियमों की पारदर्शिता और विशेष रूप से संरक्षित जनजातीय अधिकारों की अनदेखी का गंभीर उदाहरण बनता जा रहा है। विशेष पिछड़ी बैगा जनजाति जिसे देश में'राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र' के रूप में विशेष संरक्षण प्राप्त है की एक पात्र युवती ने आरोप लगाया है कि सभी योग्यता और प्राथमिकता के बावजूद उसे चयन सूची से बाहर कर दिया गया,जबकि नियमों के विपरीत एक अन्य अभ्यर्थी को नियुक्ति दे दी गई,मामले की गंभीरता इस बात से भी बढ़ जाती है कि पीड़ित युवती ने 13 जनवरी 2026 को कलेक्टर जनदर्शन में लिखित शिकायत देकर पूरे चयन प्रक्रिया की पुनः जांच की मांग की थी,लेकिन तीन महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है,इससे यह सवाल उठने लगा है कि क्या प्रशासनिक स्तर पर इस शिकायत को गंभीरता से लिया ही नहीं गया,या फिर मामला जानबूझकर लंबित रखा गया है,शिकायत में यह भी उल्लेख है कि चयनित अभ्यर्थी की निवास पात्रता ही संदिग्ध है,जबकि शिकायतकर्ता स्वयं संबंधित क्षेत्र की मूल निवासी है और नियमानुसार उसे प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी। यदि यह आरोप सही हैं,तो यह न केवल भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल है,बल्कि यह विशेष संरक्षित जनजाति के अधिकारों की सीधी अनदेखी भी मानी जाएगी,इस पूरे घटनाक्रम ने महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यप्रणाली को भी कठघरे में खड़ा कर दिया है। दस्तावेजों की जांच,पात्रता निर्धारण और चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता–तीनों पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में यह मामला केवल एक युवती के रोजगार से जुड़ा मुद्दा नहीं,बल्कि उस व्यवस्था की विश्वसनीयता का परीक्षण बन गया है, जो समाज के सबसे कमजोर वर्गों को प्राथमिकता देने का दावा करती है, अब सबसे बड़ा सवाल यही है–क्या विशेष बैगा जनजाति की इस पात्र बेटी को उसका हक मिलेगा,या उसकी शिकायत भी फाइलों में दबकर रह जाएगी?

13 जनवरी को कलेक्टर जनदर्शन में दावा-आपत्ति की शिकायत फिर भी जांच ठंडे बस्ते में...

पीड़ित युवती ने दिनांक 13/01/2026 को कलेक्टर जनदर्शन,जिला एमसीबी में लिखित आवेदन देकर दावा-आपत्ति की पुनः जांच की मांग की थी,आवेदन में उल्लेख है कि उसने कक्षा 8वीं में 66.9 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं और विशेष बैगा जनजाति से होने के कारण उसे नियमानुसार प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी, इसके बावजूद अब तक शिकायत पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से युवती न्याय के लिए भटकने को मजबूर है।

नियुक्ति पाने वाली महिला की निवास पात्रता पर उठे सवाल

शिकायत में यह भी गंभीर आरोप लगाया गया है कि जिस महिला सोनी पति स्व. सुनील की नियुक्ति की गई,वह विवाह के बाद अन्यत्र निवास कर रही है और संबंधित ग्राम क्षेत्र की मतदाता सूची में भी उसका नाम दर्ज नहीं है, और सोनी ग्राम शंकरगढ़ से विवाह होकर अन्यत्र गांव चली गई है यह प्रमाण पत्र सरपंच सचिव द्वारा प्रमाणित किया गया है, इसके बावजूद कथित रूप से नियमों और निवास पात्रता को दरकिनार कर नियुक्ति आदेश जारी कर दिया गया, जिससे स्थानीय ग्रामीणों और आवेदकों में भारी नाराजगी देखी जा रही है।

महिला बाल विकास परियोजना कार्यालय की भूमिका पर भी सवाल

मामले में परियोजना अधिकारी,महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में है,आरोप है कि दस्तावेजों में कमियां होने के बावजूद चयनित अभ्यर्थी को लाभ पहुंचाया गया, जबकि विशेष बैगा जनजाति की पात्र युवती को सूची से बाहर कर दिया गया,इससे विभागीय चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लग रहा है।

कलेक्टर से निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग...

पीड़ित परिवार और ग्रामीणों ने कलेक्टर से मांग की है कि पूरे भर्ती प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाए, दस्तावेजों की दोबारा समीक्षा हो और यदि अनियमितता साबित हो तो नियुक्ति निरस्त कर पात्र विशेष बैगा जनजाति की बेटी को न्याय दिलाया जाए, क्या विशेष पिछड़ी बैगा जनजाति की पात्र बेटी को उसका हक मिलेगा, या शिकायत फाइलों में दबकर रह जाएगी?

लापरवाही ने ली जान...डी.वी. प्रोजेक्ट कंपनी पर एफआईआर और मुआवजे की माँग...कांग्रेस ने दी चक्काजाम और घेराव की चेतावनी

परसगढ़ी हादसे से आक्रोश : मृतक परिवार को न्याय दिलाने सड़क पर उतरी कांग्रेस

-संवाददाता-

मनेंद्रगढ़,19 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)। ग्राम पंचायत परसगढ़ी तिराहे के पास हुए भीषण सड़क हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। मेडिकल कॉलेज निर्माण कार्य में लगी डी.वी. प्रोजेक्ट कंपनी के पानी टैंकर की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद स्थानीय जनता में भारी आक्रोश है।

थाने पहुँचे दिग्गज नेता,प्रशासन को अल्टीमेटम-घटना की गंभीरता को देखते हुए भरतपुर-सोनहत के पूर्व विधायक गुलाब कमरों के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने तत्काल थाने पहुँचकर थाना प्रभारी से मुलाकात की। साथ ही, मनेंद्रगढ़ एसडीएम से फोन पर चर्चा कर प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि न्याय प्रक्रिया में देरी हुई,तो कांग्रेस पार्टी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी।

कांग्रेस की प्रमुख माँगें:- एफआईआर दर्ज होः डी.वी. प्रोजेक्ट के वाहन चालक,कंपनी प्रबंधन और संबंधित लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ तत्काल आपराधिक मामला दर्ज किया जाए।

उचित मुआवजा : मृतक के परिजनों को तत्काल सम्मानजनक और न्यायोचित आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।

कड़ी निगरानी : निर्माण कार्य में लगे भारी वाहनों की गति और परिचालन पर सख्त प्रशासन निगरानी रखे, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके।

आंदोलन की चेतावनी-कांग्रेस नेताओं ने दो टूक शब्दों में कहा है कि यदि समय रहते प्रशासन ने ठोस कदम नहीं उठाए, तो होने वाले व्यापक जनआंदोलन और घेराव की समस्त जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

इनका कहना है...

यह मात्र एक हादसा नहीं, बल्कि प्रबंधन की लापरवाही से की गई हत्या है। निर्माण कंपनियाँ नियमों को ताक पर रखकर काम कर रही हैं और प्रशासन मौन है। यदि दोषियों पर कठोर कार्रवाई नहीं हुई, तो कांग्रेस सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेगी। '

गुलाब कमरों,पूर्व विधायक (भरतपुर-सोनहत)

'निगरानी तंत्र पूरी तरह फेल हो चुका है,जिसका खामियाजा आम जनता को अपनी जान देकर भुगतना पड़ रहा है,मृतक परिवार को न्याय मिलने तक हम शांत नहीं बैठेंगे। प्रशासन की ढिलाई पर थाना और कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। '

रमेश सिंह,विधायक प्रत्याशी (मनेंद्रगढ़)

प्रेस एंड मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन की अहम बैठक संपन्न

रायपुर कार्यालय में संगठन विस्तार और भविष्य की योजनाओं पर मंथन

-संवाददाता-

रायपुर/कोरिया,19 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)। राजधानी रायपुर स्थित प्रेस एंड मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन के कार्यालय में विगत दिनों एक महत्वपूर्ण प्रादेशिक बैठक का आयोजन किया गया। संगठन के संस्थापक मनोज पाण्डेय की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में प्रदेश भर से आए प्रमुख पदाधिकारियों और सदस्यों ने हिस्सा लिया।

तीन घंटे तक चला 'मंथन'- बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु संगठन का विस्तार और पत्रकारों के हितों की सुरक्षा रहा, लगभग 3 घंटे तक चली इस सार्थक चर्चा के दौरान संगठन की मजबूती को लेकर गहन विचार-विमर्श किया गया। संस्थापक मनोज पाण्डेय ने अपने संबोधन में कहा कि 'संगठन की असली ताकत उसके सदस्य और उनकी एकता है।' उन्होंने प्रदेश के कोने-कोने तक एसोसिएशन की पहुँच बनाने और ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले पत्रकारों को जोड़ने पर विशेष बल दिया।

प्रमुख बिंदुओं पर हुई चर्चा:

संगठन का विस्तार: आगामी महीनों में जिला और ब्लॉक स्तर पर नई नियुक्तियों और समितियों के गठन की योजना बनाई गई।

पत्रकार हित: फील्ड में काम करने वाले पत्रकारों को आने वाली समस्याओं और उनके निराकरण के लिए ठोस कदम उठाने पर सहमति बनी।

लोकतांत्रिक प्रक्रिया: बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों और सदस्यों ने खुले मन से अपनी राय रखी, जिससे चर्चा और भी जीवंत और प्रभावी रही।

बैठक लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय-बैठक के समापन सत्र में सर्वसम्मति से कई अहम फैसले लिए गए, जो आने वाले समय में संगठन को नई ऊंचाईयों पर ले जाएंगे, पदाधिकारियों ने भविष्य की गतिविधियों की रूपरेखा तैयार की और संकल्प लिया कि वे एक एकजुट होकर मीडिया जगत के कल्याण के लिए कार्य करेंगे, 'यह बैठक मात्र एक चर्चा नहीं थी, बल्कि संगठन के भविष्य की नींव है,हम सबको मिलकर एक ऐसा मंच तैयार करना है जहाँ हर पत्रकार स्वयं को सुरक्षित और गौरवान्वित महसूस करे।

भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में 5400 विद्यार्थियों की भागीदारी,मेधावी छात्र-छात्राएं सम्मानित

-संवाददाता-

सूरजपुर,18 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)। गायत्री तीर्थ शांतिकुंज हरिद्वार के तत्वावधान में आयोजित भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा 2025-26 में शामिल विद्यार्थियों का जिला स्तरीय सम्मान समारोह शनिवार को गायत्री शक्तिपीठ सूरजपुर में आयोजित किया गया,इस परीक्षा में जिले भर से लगभग 5400 छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया,जो भारतीय संस्कृति और मूल्य आधारित शिक्षा के प्रति बढ़ती रुचि को दर्शाता है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि केपी शर्मा,संचालक ग्लोबल पब्लिक स्कूल सूरजपुर द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया, समारोह में कक्षा 5वीं से 12वीं तक के प्रतिभागियों को प्रावीण्य सूची के आधार पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने पर शील्ड,पुरस्कार राशि एवं साहित्य देकर सम्मानित किया गया,अपने संबोधन में मुख्य अतिथि केपी शर्मा ने गुरुदेव आचार्य श्रीराम शर्मा के जीवन दर्शन,उनके द्वारा स्थापित मानवीय मूल्यों एवं गायत्री परिवार की विभिन्न योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की परीक्षाएं विद्यार्थियों में नैतिकता,संस्कार और भारतीय परंपराओं के प्रति जागरूकता विकसित करती हैं,जिला समन्वयक शिव शंकर कुशवाहा ने परीक्षा की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि यह परीक्षा विद्यार्थियों में ज्ञानवर्धन के साथ-साथ चरित्र निर्माण का भी महत्वपूर्ण माध्यम है,उन्होंने बताया कि प्रत्येक कक्षा के अनुसार नाममात्र शुल्क लेकर पंजीयन किया जाता है और प्रतिभागियों को उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, साथ ही उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को जिला स्तर के साथ-साथ राज्य स्तर पर भी सम्मानित किया जाता है, इस अवसर पर जिले के लिए गर्व की बात यह रही कि शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय केरता, प्रतापपुर की कक्षा 8वीं की छात्रा कुमारी पूजा (पिता राम नरेश) का चयन राज्य स्तरीय सम्मान के लिए हुआ है,उन्हें आगामी 25 अप्रैल को रायपुर स्थित गायत्री शक्तिपीठ समता कॉलोनी में आयोजित समारोह में सम्मानित किया जाएगा,कार्यक्रम के सफल आयोजन में चन्द्रशेखर साहू, विष्णु प्रजापति,गोपाल सिंह, हरिहर वर्मा,अवधेश गोयल, पवन कुमार गर्ग,लोचन प्रसाद गुप्ता एवं जवाहर राजवाड़े का विशेष योगदान रहा,अंत में सुशील कुमार निगम द्वारा आभार प्रदर्शन किया गया,यह आयोजन न केवल विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक रहा,बल्कि भारतीय संस्कृति और संस्कारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास भी साबित हुआ।

न्यायालय नज़ूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,छ0ग0

रा0प्र0क्र0-121/202601021200112/अ-6/2022-23

ईश्तहार

1. श्रीमती श्रीदेवी नम्बुदिरी पति ईश्वरन विष्णु नम्बुदिरी, उम्र- 72 वर्ष
2. विष्णु नारायणन नम्बुदिरी आ0 ईश्वरन विष्णु नम्बुदिरी, उम्र 40 वर्ष
3. श्रीमती सरिता नम्बुदिरी पति स्व. विष्णु ईश्वरन नम्बुदिरी, उम्र- 41 वर्ष
4. हर्षित नम्बूदिरी आ0 स्व. विष्णु ईश्वरन नम्बुदिरी, उम्र 18 वर्ष

सभी निवासी भट्ठी रोड़ त्रिकोण चौक के पास अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ0ग0)

.....आवेदकगण

प्रति

श्रीदेवी पति रजनीश, उम्र- 46 वर्ष
वर्तमान निवासी- ऐ-103 शितल स्मृति,शितलनगर अपोजिट (oppsite hethway) ब्राड वे आफिस एम0टी0एन0एल0, मीरा रोड़ ई- मुम्बई (मुम्बई)

......अनावेदिका

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि अनावेदिका श्रीदेवी पति रजनीश, उम्र- 46 वर्ष, वर्तमान निवासी - ऐ-103 शितल स्मृति, शितलनगर अपोजिट (opp-site hethway) ब्राड वे आफिस एम0टी0एन0एल0, मीरा रोड़ ई- मुम्बई (मुम्बई) को सूचित किया जाता है, कि आवेदक की ओर अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में शीट क्रमांक 04, मोहल्ला-केदारपुर, नगर अम्बिकापुर स्थित भूखण्ड क्रमांक 1980/22, 1980 / 26 रकबा क्रमशः 0.06, 0.035 एकड़ में नामांतरण संशोधन का मामला निराकरण हेतु प्रचलित है, इस मामले में सुनवाई दिनांक 05.05.2026 को दिन के समय 02.00 बजे नियत है। श्रीदेवी पति रजनीश, उम्र- 46 वर्ष का ज्ञात पता सही नहीं होने के कारण नोटिस तामीली नहीं हो पा रहा है। अतः जरिए ईश्तहार अनावेदिका श्रीदेवी पति रजनीश को सूचित किया जाता है, कि आप स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से नियत तिथि एवं समय पर अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। आपकी अनुपस्थिति में आपके विरूद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी । नियत तिथि पर अवकाश की स्थिति में आगामी कार्य दिवस पर प्रकरण में सुनवाई किया जावेगा ।

अतः उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो वे अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वंय अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 05/05/2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/अपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

आज दिनांक 17/04/2026 को मेरे न्यायालयीन मुद्रा एंव हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(सील)

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर,सरगुजा

न्यायालय तहसीलदार लटोरी जिला-सूरपजुर,छ0ग0

रा0प्र0क्र0 /ब-121 वर्ष
ग्राम - प0ह0न0........

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक राजू राजवाड़े आ0 स्व- रामसूरत जाति रजवार निवासी ग्राम कल्याणपुर प0ह0न0 ....रा0नि0म0... तहसील लटोरी जिला सूरजपुर छ0ग0 द्वारा आवेदन पेश किया गया है, कि आवेदक के पिता-रामसूरत का मृत्यु दिनांक 09/01/1980 को ग्राम कल्याणपुर में हुई है, अज्ञानतावश मृत्यु पंजीयन हेतु ग्राम पंचायत कल्याणपुर को आदेशित करने आवेदन पेश किया है। जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोईआपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से पेशी दिनांक 28/04/26 तक अपना आपत्ति आपत्ति इस न्यायायल में पेश कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 10/4/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया ।

पेशी दिनाक - 28/4/26 जारी दिनांक -10/4/26

(सील)

कार्यपालिक दण्डाधिकारी
लटोरी,जिला-सूरजपुर

घुनघुट्टा रिसोर्ट पर 'प्रशासनिक ग्रहण': कागजों पर हैंडओवर

जमीन पर ताला,आखिर कब खत्म होगा सैलानियों का इंतजार?

पर्यटन विभाग की सुस्ती या कोई और मजबूरी? जनवरी में मिला हैंडओवर,फिर भी अप्रैल तक क्यों नहीं चालू हुआ घुनघुट्टा रिसोर्ट?

घुनघुट्टा रिसोर्ट या रसूखदारों का 'प्राइवेट विला'? करोड़ों के पर्यटन स्थल पर प्रबंधन का कब्जा,आम जनता के लिए आज भी 'नो एंट्री'! '

राजन पाण्डेय

कोरिया/सोनहत,19 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)। प्रकृति की गोद में बसे सोनहत के घुनघुट्टा रिसोर्ट को लेकर प्रशासन की कार्यप्रणाली अब सवालों के घेरे में है। चौंकाने वाली बात यह है कि जनवरी 2026 में ही यह प्रोजेक्ट पर्यटन विभाग को हैंडओवर किया जा चुका है, लेकिन विडंबना देखिए कि 4 माह बीत जाने के बाद भी इसे आम जनता के लिए सुचारू रूप से शुरू नहीं किया जा सका है। करोड़ों की लागत से तैयार यह सरकारी संपत्ति अब केवल अव्यवस्था और प्रबंधन की तानाशाही का केंद्र बनकर रह गई है। जनवरी 2026 में उठी विरोध की लहर के बाद उम्मीद थी कि व्यवस्थाएं सुधरेंगी, लेकिन हकीकत यह है कि महीनों बीत जाने के बाद भी यह रिसोर्ट आम पर्यटकों के लिए पूरी तरह 'चालू' नहीं हो सका है।

चेहरा देखकर खुलता है गेट, आम आदमी के लिए 'ऊपर' का आदेश अनिवार्य

हैरानी की बात यह है कि रिसोर्ट में प्रवेश के लिए आज भी कोई पारदर्शी नियमावली नहीं है, स्थानीय लोगों और पर्यटकों का आरोप है कि यहाँ 'चेहरा देखकर' प्रवेश दिया जाता है,यदि आप रसूखदार हैं या किसी बड़े अधिकारी या नेता के परिचित, तो आपके लिए रेड कार्पेट बिछा है, लेकिन यदि आप एक साधारण पर्यटक हैं जो परिवार के साथ सुकून के दो पल बिताने आए हैं, तो आपको गेट से ही 'ऊपर बात कर लीजिए' का रटा-रटाया जवाब देकर लौटा दिया जाता है, सुधार के नाम पर सिर्फ 'बोलचाल' में बदलाव, सुविधाओं पर ताला जनवरी में यूथ कांग्रेस और स्थानीय मीडिया के कड़े रुख के बाद कर्मचारियों के लहजे में थोड़ी नरमी तो आई है, लेकिन रिसोर्ट के पूर्ण संचालन में हो रही 'अत्यधिक देरी' कई सवाल खड़े कर रही है।

सोनहत के पर्यटन व्यवसाय को गहरा जख्म

कांग्रेस नेता अनित दुबे और यूथ कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र साहू द्वारा पूर्व में जताई गई आशंकाएं अब सच साबित हो रही हैं, बाहर से आने वाले पर्यटक अब सोनहत का रुख करने से कतराने लगे हैं, घुनघुट्टा के नाम पर जो 'अघोषित पाबंदी' चल रही है, उसने न केवल रिसोर्ट बल्कि सोनहत के छोटे दुकानदारों के रोजगार पर भी बुरा असर डाला है।

स्थानीय प्रशासन के मौन पर उठ रहे सवाल

खण्ड स्तर के स्थानीय प्रशासन तक बात पहुँचने के बावजूद, धरातल पर स्थिति जस की तस बनी हुई है, रिसोर्ट के बाहर आज भी कोई 'साइन बोर्ड' या 'विजिटिंग गाइडलाइन' नहीं है, जिससे पर्यटकों को पता चल सके कि अंदर जाने की पात्रता क्या है।

अंत कुछ सवाल-

- सवाल 1: जब करोड़ों रुपए खर्च कर इसे पर्यटकों के लिए बनाया गया, तो आम जनता इससे वंचित क्यों है?
- सवाल 2: क्या रिसोर्ट का प्रबंधन स्थानीय प्रशासन के नियंत्रण में है या जिले के बाहर बैठे किसी 'अदृश्य' सत्ता के इशारे पर चल रहा है?
- सवाल 3: शाम 4 बजे के बाद आने वाले पर्यटकों के लिए नियम इतने कठोर क्यों हैं कि उन्हें गेट से मायूस होकर लौटना पड़ता है?

इनका कहना है...

अगर जल्द ही घुनघुट्टा रिसोर्ट को सभी के लिए समान रूप से नहीं खोला गया और 'ऊपर बात कर लीजिए' वाली तानाशाही संस्कृति खत्म नहीं हुई, तो वह दिन दूर नहीं जब यह शानदार पर्यटन स्थल केवल एक 'प्राइवेट विला' बनकर रह जाएगा। जनता अब जवाब चाहती है-घुनघुट्टा रिसोर्ट आम आदमी के लिए कब खुलेगा?

प्रकाश चन्द्र साहू
सोनहत

यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस घुनघुट्टा रिसोर्ट को सोनहत और कोरिया जिले की पर्यटन पहचान बनाने के लिए विकसित किया गया, वह आज प्रबंधन की मनमानी का अड्डा बन चुका है, हमें जानकारी मिली है कि जनवरी 2026 में ही यह पर्यटन विभाग को हैंडओवर हो चुका है, फिर भी 4 महीने बीत जाने के बाद इसे आम जनता के लिए क्यों नहीं खोला गया? क्या विभाग किसी खास 'मुहूर्त' का इंतजार कर रहा है या इसे केवल वीआईपी लोगों की ऐशगाह बनाकर रखने की योजना है? '

अनित दुबे जिला महामंत्री,कांग्रेस कमेटी

सोनहत का घुनघुट्टा रिसोर्ट हमारे जिले की सुंदरता का प्रतीक है,लेकिन पिछले कुछ समय से वहां पर्यटकों को हो रही असुविधा की शिकायतें मुझ तक लगातार पहुँच रही हैं। कई पर्यटकों ने मुझे फोन कर अपनी नाराजगी जाहिर की है कि उन्हें रिसोर्ट के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। इसके अलावा,क्षेत्र के अनेक लोगों ने व्यक्तिगत रूप से और फोन के माध्यम से मुझ से यह मांग की है कि इस भव्य रिसोर्ट का संचालन जल्द से जल्द विधिवत रूप से शुरू किया जाए।' मैं इस विषय को बेहद गंभीरता से ले रहा हूँ और जल्द ही जिला प्रशासन व संबंधित विभाग के अधिकारियों से इस संबंध में विस्तृत चर्चा करूँगा। मेरा हर संभव प्रयास रहेगा कि जो भी तकनीकी या प्रशासनिक बाधाएं हैं, उन्हें दूर कर इस रिसोर्ट को शीघ्र अति शीघ्र आम पर्यटकों के लिए पूरी तरह चालू कराया जाए, ताकि सोनहत के पर्यटन को नई गति मिल सके। '

देवेंद्र तिवारी,जिलाध्यक्ष भाजपा कोरिया

छत्तीसगढ़ राज्य अधिवक्ता परिषद कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष बने प्रवीण गुप्ता....

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,19 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ राज्य अधिवक्ता परिषद के चुनाव में अधिवक्ता प्रवीण गुप्ता कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनके निर्वाचित होने पर अधिवक्ता जगत सहित समर्थकों में खुशी की लहर है और उन्हें लगातार बधाइयां दी जा रही हैं। जानकारी के अनुसार,चुनाव प्रक्रिया शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता एवं महाधिवक्ता छत्तीसगढ़ शासन की उपस्थिति में संपन्न हुई। इसमें कार्यकारिणी समिति के चेयरमैन पद पर प्रवीण गुप्ता निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। इसके अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य पद पर शैलेन्द्र दुबे, अध्यक्ष पद पर रवींद्र पाराशर तथा कोषाध्यक्ष पद पर नरेंद्र सोनी निर्वाचित हुए। बताया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य अधिवक्ता परिषद प्रदेश के लगभग 34 हजार अधिवक्ताओं का प्रतिनिधित्व करता है। प्रवीण गुप्ता इससे पहले भी वर्ष 2007, 2014 और 2025 में लगातार तीसरी बार स्टेट बार काउंसिल चुनाव जीत चुके हैं। प्रवीण गुप्ता के अध्यक्ष बनने पर अधिवक्ताओं एवं शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई देते हुए सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी हैं।

आंगनबाड़ी साड़ी खरीदी घोटाले के विरोध में मंत्री का पुतला दहन,महिला कांग्रेस ने की निष्पक्ष जांच और इस्तीफे की मांग

-संवाददाता-
कोरिया,19 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए साड़ी खरीदी में कथित अनियमितताओं को लेकर कोरिया जिले में सियासी माहौल गरमा गया है, रविवार को महिला कांग्रेस कोरिया ने जिला मुख्यालय बैकुंठपुर के कुमार चौक पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का पुतला दहन किया और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के साथ उनके इस्तीफे की मांग उठाई, यह प्रदर्शन प्रदेश महिला कांग्रेस के आह्वान पर आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए।

साड़ी खरीदी में करोड़ों की अनियमितता का आरोप-महिला कांग्रेस पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि प्रदेश में लगभग 1.94 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए साड़ी खरीदी में करीब 9.7 करोड़ रुपये की अनियमितता हुई है, उनका कहना है कि खादी ग्रामोद्योग विभाग के माध्यम से की गई खरीदी में गुणवत्ता को नजरअंदाज किया गया और मानकों का पालन नहीं किया गया, आरोपों के अनुसार,जहां साड़ियों की निर्धारित लंबाई 5.5 से 6.3 मीटर होनी चाहिए थी, वहां करीब 5 मीटर की साड़ियां वितरित की गई,इसके साथ ही बाजार में कम कीमत की साड़ियों को अधिक मूल्य पर दिखाकर आपूर्ति करने का भी आरोप लगाया गया। इस पूरे प्रकरण को महिला कांग्रेस ने 'संगठित आर्थिक गड़बड़ी' करार दिया है।

महिला कांग्रेस का प्रदर्शन और नारेबाजी- प्रदर्शन का नेतृत्व जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष संजोती मरकाम ने किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मंत्री के खिलाफ विरोध जताते हुए पुतला दहन किया गया और मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की गई,प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जो समाज के सबसे महत्वपूर्ण वर्ग–महिलाओं और बच्चों–के लिए कार्य करती हैं, उनके साथ इस तरह की लापरवाही और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

इस्तीफे और उच्च स्तरीय जांच की मांग- महिला कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री से मांग की कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराई जाए,उनका कहना है कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और संबंधित मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए,नेताओं ने यह भी कहा कि यह मामला केवल साड़ी खरीदी तक सीमित नहीं है,बल्कि यह प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही का मुद्दा है,जिसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी-इस प्रदर्शन में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, पूर्व विधायक अंबिका सिंह देव,पूर्व जिलाध्यक्ष नजीर अजहर सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद रहे। इसके अलावा अजय सिंह, मनोज दुबे,हेमसागर यादव,बृजवासी तिवारी,बिहारी लाल राजवाड़े,आशीष यादव, विपुल शुक्ला,प्रांजल जायसवाल,मोनू माझी, रियाजउद्दीन,फारूक,वसीम खान,इब्राहिम, चांदनी सोनी,ममता गुप्ता,महिंदर कौर,कादिर अली,गोल्डन टेलर,उर्मिला रानी राजवाड़े, दुर्गा, प्रेमा,भगवती, रामबाई सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

राजनीतिक तापमान बढ़ा,आगे और आंदोलन के संकेत- इस प्रदर्शन के बाद जिले में सियासी माहौल और गरमाने की संभावना जताई जा रही है,महिला कांग्रेस ने संकेत दिए हैं कि यदि जल्द ही मामले में कार्रवाई नहीं होती,तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।

जवाबदेही तय होने का इंतजार- आंगनबाड़ी साड़ी खरीदी का यह मामला अब राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों ही स्तरों पर चर्चा का विषय बन चुका है, आरोप गंभीर हैं और यदि इनमें सच्चाई पाई जाती है,तो यह बड़े स्तर की अनियमितता साबित हो सकती है,अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि शासन इस मामले में क्या रुख अपनाता है–क्या निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी,या यह मामला भी समय के साथ ठंडे बस्ते में चला जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले को दी ऐतिहासिक सौगात...133 गांवों में लो वोल्टेज की समस्या होगी खत्म,लगाए जाएंगे अतिरिक्त ट्रांसफार्मर...

-संवाददाता-
जशपुरनगर,19 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।

जिले के लोगों के लिए राहत भरी बड़ी खबर सामने आई है। लंबे समय से लो वोल्टेज की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों को अब जल्द ही इस परेशानी से निजात मिलने वाली है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर जिले के 133 गांव, नगर एवं टोला-मुहल्लों में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्थापित किए जाएंगे।जिससे जिले की बिजली आपूर्ति में सुधार होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार होने वाली बिजली की समस्या का स्थायी समाधान मिल सकेगा। खासकर किसानों, छात्रों और छोटे व्यवसायियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।

विद्युत के क्षेत्र में जशपुर को मिल चुकी है कई बड़ी सौगात

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जिले को विद्युत विकास के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है।400 केवी उपकेंद्र कुनकुरी के हर्राडांड में प्रदेश का 5वां सबसे बड़ा 400/220 केवी का अत्याधुनिक उपकेंद्र स्थापित किया जा रहा है।साथ ही नए सब-स्टेशन (33/11 केवी): ये सब-स्टेशन सलिहाटोली, विपतपुर, भगोरा, समडमा, मैनी, रेड़े, पालीडीह, खुटेरा एवं चेटवा सहित अन्य स्थानों पर निर्मित किए जाएंगे। एवं उच्च क्षमता केंद्र दू फरसाबहार और झिक्की बगीचा में 132/33 केवी के सब-स्टेशन स्वीकृत हैं।

विकास को मिलेगी नई गति, जिलेवासियों ने मुख्यमंत्री का जताया आभार : इन योजनाओं के लागू होने से बिजली की गुणवत्ता में सुधार होगा साथ ही लो वोल्टेज और ट्रिपिंग की समस्या खत्म होगी औद्योगिक एवं कृषि कार्यों को गति मिलेगी तथा ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार आएगा, विद्युत विभाग में बड़ी सौगात मिलने के बाद जिले भर में खुशी का माहौल है। स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त करते हुए इसे क्षेत्र के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है।

वृद्धाश्रम में मना बंगाली नववर्ष,जरूरतमंदों को बांटी सामग्री

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,19 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।

आदया बंग समिति द्वारा बंगाली नववर्ष 'पहला बैशाख' के अवसर पर एक सराहनीय सामाजिक पहल करते हुए स्थानीय वृद्धाश्रम में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान समिति की महिलाओं ने बुजुर्गों के साथ समय बिताया,उनसे बातचीत की और उनकी जरूरतों को समझा। कार्यक्रम में आश्रम के वृद्धजनों को फल, आवश्यक सामग्री एवं अन्य उपयोगी वस्तुएं वितरित की गईं। उपस्थित सदस्यों ने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर नववर्ष की शुभकामनाएं प्राप्त कीं। इस अवसर पर हेना सेन, आतिशी भटाचार्य, संगीता मुखर्जी और रीना पॉल सहित अन्य सदस्य मौजूद रहीं। कार्यक्रम का नेतृत्व संस्थापिका वंदना दत्ता ने किया।

कोरबा में बड़ा हादसा...राखड़ डेम फटने से जेसीबी ड्राइवर की मौत,मलबे में दबा वाहन

-संवाददाता-
कोरबा,19 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)।

जिले में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब झाबू गांव स्थित सीएसईबी राखड़ डेम अचानक फट गया। इस हादसे में एक जेसीबी मशीन मलबे में दब गई और उसका ऑपरेटर जिंदा दफन हो गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, यह राखड़ डेम बिजली संयंत्रों से निकलने वाले कोयले की राख (फ्लाई ऐश) से बनाया गया था। प्रारंभिक रूप से माना जा रहा है कि संरचना में कमजोरी और लापरवाही के कारण डेम टूट गया, जिससे भारी मात्रा में राख और पानी नीचे की ओर बहने लगा। हादसे के समय जेसीबी मशीन मौके पर कार्य कर रही थी, जो अचानक आए मलबे की चपेट में आ गई। मशीन का ऑपरेटर बाहर निकल नहीं सका और मलबे में दबकर उसकी मौत हो गई। घटना के बाद संयंत्र में काम कर रहे मजदूरों ने ही राहत कार्य शुरू किया। हालांकि, प्रशासनिक अमले के मौके पर पहुंचने की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।

90 दशक का सिंगर,गर्लफ्रेंड के मर्डर की झूठी कहानी से हुआ फेमस

आज भी दिल टूटे आशिकों की जुबान पर रहता है इनका गाना

90 के दशक में अताउल्लाह खान का बेदर्दी से प्यार एल्बम खूब चला। इसे हिट कराने के लिए उनकी गर्लफ्रेंड के मर्डर की झूठी कहानी गढ़ी गई थी, जिससे लोगों में सहानुभूति जगी और कैसेट की बिक्री बढ़ी। 90 के दशक में बॉलीवुड में कुमार सानू ,नदीम श्रवण जैसे

सिंगर्स का दौर था। उस वक्त एक से बढ़कर एक रोमांटिक गाने रिलीज हो रहे थे। इस दौर में अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का,दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, मुझको दफनाकर जब वो वापस जाएंगे जैसे दर्दभरे गानें बाजार में आते ही हिट हो गए।

गुलशन कुमार ने निकाली थी एल्बम

इन गानों को गाने वाले सिंगर का नाम था अताउल्लाह खान। तब भारत में कैसेट चलते थे। जैसे ही ये आए हाथों-हाथ ये कैसेट्स मार्केट में बिकने लगी। 1992 में टी-सीरीज के गुलशन कुमार ने पाकिस्तानी सिंगर अताउल्लाह खान का म्यूजिक एल्बम रिकॉर्ड किया और इसे 'बेदर्दी से प्यार' नाम से लॉन्च किया। इस एल्बम में कुल 8 गाने थे। ओ दिल तो के हंसती हो मेरा', 'मुझको ये तेरी बेवफाई मार डालेगी,'देख ले आके जरा चैन से सोने वाले','मैं दुनिया तेरी छो चला', 'मुझको दफनाकर जव वो वापस जाएंगे', 'अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का', 'बेदर्दी से प्यार का सहारा न मिला', 'तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए' इसका हिस्सा थे। यह एल्बम सुपरहिट हुई और सड़कों पर दौड़ते ट्रकों और ऑटो में ये गाने खूब सुनाई देते थे।

क्या गढ़ी गई थी झूठी कहानी?

लेकिन क्या आपको पता है कि इन गाने को हिट कराने के लिए एक झूठी कहानी रची गई थी?

अब ये किसने फैलाई ये तो हमें नहीं पता लेकिन उस वक्त ऐसी चर्चा हुई कि अताउल्लाह खान किसी लड़की से प्यार करते थे जिसने उन्हें धोखा दे दिया। अताउल्लाह खान ने उस लड़की की हत्या कर दी और पाकिस्तान की जेल में बंद हैं।कहानी में आगे कहा गया कि गायक ने जेल की सजा काटी और वहीं से उन्होंने दिल टूटने और प्यार में धोखा मिलने जैसे विषयों पर जेल से ही गाना शुरू कर दिया है। हालांकि ये कहानी झूठी थी लेकिन इस झूठी कहानी का फायदा म्यूजिक कंपनी टी सीरीज को खूब हुआ। लोगों में अताउल्लाख खान के प्रति हमदर्दी जगी और ज्यादा से ज्यादा संख्या में कैसेट खरीदे गए।

चमक गई थी सोनू निगम की किस्मत

गुलशन कुमार ने फिर अपने भाई कृष्ण कुमार के साथ मिलकर एक फिल्म बेवफा सनम बनाई. बेवफा फिल्म के गानों ने दोनों देशों में धूम मचा दी। इसी फिल्म के गाने अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का गाकर सोनू निगम की किस्मत चमक गई। अताउल्लाह खान ने अपने गीतों की रचना के लिए फारूक रोखरी, मलिक सोना खान, मुनव्वर अली मलिक,फाता खान और ईसाखेल के कई कम प्रसिद्ध कवियों की कविताओं का चयन किया है।

संजीव कुमार से सगाई,एक शर्त की वजह से टूटा रिश्ता

एक्टिंग छोड़ साध्वी बनीं एक्ट्रेस अब देती हैं प्रवचन

नीता मेहता की संजीव कुमार से सगाई उनकी एक शर्त के कारण टूट गई,क्योंकि संजीव उन्हें गृहिणी बनाना चाहते थे। इसके बाद नीता ने अभिनय जारी रखा,लेकिन उन्हें अपेक्षित पहचान नहीं मिली। आज के समय में कई सारी ऐसी एक्ट्रेसेज हैं जो शादी के बाद भी फिल्मों में काम कर रही हैं। दीपिका पादुकोण,आलिया भट्ट), कियारा आडवाणी) ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि पहले के जमाने में ये उतना आसान नहीं था। एक्ट्रेसेज को लगता था कि शादी के बाद उनका करियर खत्म हो जाएगा या फिर उन्हें उतनी फिल्मों के ऑफर नहीं मिलेंगे।

संजीव कुमार से होने वाली थी शादी

तब के जमाने की सोच भी वैसी ही थी कि एक्ट्रेसेज को शादी के बाद घर का काम धंधा संभालने के लिए हाउसवाइफ बनना पड़ता था। 80 के दशक के एक्टर संजीव कुमार की नीता मेहता से ऐसी ही कुछ अपेक्षा थी। दोनों कलाकार एक-दूसरे से बेहद प्यार करते थे और शादी के बंधन में भी बंधने वाले थे। लेकिन फिर इस रिश्ते में एक बाधा आ गई। खबरों के अनुसार,संजीव कुमार शादी के बाद नीता को अभिनेत्री के बजाय हाउसवाइफ के तौर पर देखना चाहते थे लेकिन नीता को यह मंजूर नहीं था। दुर्भाग्यवश,दोनों को अलग होना पड़ा।

40 से ज्यादा फिल्मों में कर चुकी हैं काम

इस रिश्ते के दुखद अंत के बाद,नीता ने कथित तौर पर हिम्मत दिखाते हुए हालात का सामना किया और 90 के दशक तक फिल्मों में काम करती रहीं। रिश्ता कागज का,औरत औरत औरत और पत्थर से टक्कर उनकी कुछ मशहूर फिल्में हैं। लगभग 40 फिल्मों में काम करने के बावजूद,नीता को फिल्म इंडस्ट्री में वो पहचान नहीं मिली जिसकी उन्हें चाह थी। इससे उन्हें काफी निराशा हुई होगी क्योंकि अभिनय के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था।

खबरों के मुताबिक,नीता का परिवार फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाने के उनके फैसले के खिलाफ था। नीता ने हिम्मत जुटाई और परिवार के फैसले के खिलाफ जाने का फैसला किया। लगता है किस्मत ने भी उनका साथ दिया और उन्हें प्रतिष्ठित फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एफटीआईआई) में दाखिला मिल गया।

एक्ट्रेस ने क्यों छोड़ी फिल्में?

एफटीआईआई में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्हें पोंगा पंडित और ये है जिंदगी जैसी फिल्मों में कुछ भूमिकाएं निभाने का मौका मिला। उनके जीवन का सबसे बड़ा ब्रेक तब आया जब उन्हें फिल्म %मैं तुलसी तेरे आंगन की में नैनी की भूमिका निभाने का ऑफर मिला। हालांकि, वह अपनी लोकप्रियता का फायदा नहीं उठा सकीं और 80 के दशक के अंत के बाद,उन्हें फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं मिलना बंद हो गईं। जल्द ही, उन्होंने फिल्मी करियर को अलविदा कहने का फैसला किया और एक ज्वेलरी शॉप शुरू कर दी।
इसके बाद उनकी स्प्रिचुअल जर्नी की शुरुआत हुई,वह गुरु मां आनंदमयी से प्रेरित हुईं,उन पर एक किताब लिखी। फिलहाल, नीता मुंबई में रहती हैं और यूट्यूब पर योग से संबंधित वीडियो डालती हैं। वहीं संजीव कुमार का 6 नवंबर,1985 को 47 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।

36 साल पहले सनी देओल ने मिथुन चक्रवर्ती से छीन ली थी फिल्म

पिता धर्मेंद्र की वजह से बदली गई थी कास्ट

36 साल पहले सनी देओल की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म रिलीज हुई थी, जिसके लिए पहली पसंद मिथुन चक्रवर्ती थे। सनी देओल हिंदी सिनेमा के सबसे दमदार अभिनेताओं में से एक हैं। 80 के दशक से लेकर अब तक बतौर एक्टर वह अपनी शानदार मूवीज के जरिए फैंस का भरपूर मनोरंजन करते हुए नजर आ रहे हैं। 90 के दशक में सनी ने अपने करियर की सबसे ज्यादा कल्ट और क्लासिक दीं। उनमें से एक फिल्म ऐसी थी, जिसके लिए सनी देओल मेकर्स की पहली पसंद नहीं थे और उस फिल्म को अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती करने वाले थे। लेकिन धर्मेंद्र की वजह से वह फिल्म सनी को झोली में आई थी।

सनी देओल को ऐसी मिली थी कल्ट फिल्म

निर्देशक राजकुमार संतोषी के साथ सनी देओल की जोड़ी काफी सफल रही है। इस दोनों ने 1990 में आई फिल्म घायल के जरिए शुरुआत की थी। लेकिन घायल की कास्टिंग की कहानी काफी रोचक है। आईएमडीबी की रिपोर्ट के अनुसार संतोषी इस मूवी में पहले धर्मेंद्र को कास्ट करने वाले थे, लेकिन बढ़ती उम्र की वजह से उन्होंने इस मूवी को मना कर दिया। हालांकि, उन्हें घायल की कहानी काफी पसंद आई थी। बाद में राजकुमार संतोषी ने अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती संग घायल को बनाने की योजना बनाई और मिथुन इसके लिए लगभग तैयार हो गए थे। लेकिन बाद में राजकुमार के पास धर्मेंद्र जी का कॉल पहुंचा और उन्होंने कहा...तुम ये फिल्म मेरे बेटे सनी के साथ बना सकते हो,वह मूवी के किरदार में एक दम फिट बैठेगा और फिर इसके बाद राजकुमार संतोषी का दिमाग घूमा और उन्होंने सनी को घायल के लिए फाइनल कर लिया। इस तरह से हिंदी सिनेमा के एक कल्ट मूवी मिली। सनी के अलावा इस मूवी में अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री और अमरीश पुरी ने अहम भूमिकाओं को अदा किया था। बता दें कि घायल 1990 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बनी थी।

सिंगर ममता शर्मा ने बताया कैसे हुई थी आ रे प्रीतम प्यारे की शूटिंग, बोलीं- मुझमें इतनी एनर्जी कैसे आई?

ममता शर्मा ने फिल्म राउडी राठौड़ के गाने आ रे प्रीतम प्यारे की रिकॉर्डिंग का दिलचस्प अनुभव शेयर किया। ममता ने बताया कि जिसे वह पहले सिर्फ एक वॉयस चेक समझ रही थीं उसने उनके करियर की कहानी ही बदल दी। कोई गाना हो या फिल्म उनके बनने की कोई न कोई कहानी

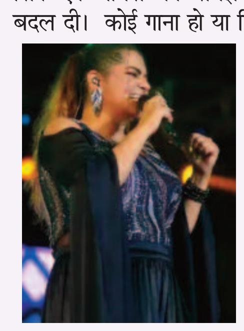

होती ही है। मुन्नी बदनाम हुई...अनारकली डिस्को चली...की गायिका ममता शर्मा ने कई गाने गाए हैं,लेकिन अब भी राउडी राठौड़ फिल्म का गाना आ रे प्रीतम प्यारे... उनका सबसे पसंदीदा है,क्योंकि इस गाने का बनाने की प्रक्रिया उनके लिए बेहद मजेदार रही है।

आवाज चेक कराने गई थीं ममता

ममता कहती हैं कि इस फिल्म के गाने के लिए मुझे एक बार रात के दस बजे साजिद-वाजिद (संगीतकार) का फोन आया है कि क्या कर रही हो। कल एक डबिंग है, एक गाने पर काम कर रहे हैं, देखना है कि तुम्हारी आवाज पर कैसा लगेगा। मैंने कहा कि मैं तो कल हूं ही नहीं, मुझे सुबह सात बजे एयरपोर्ट पहुंचना है। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा एक-दो घंटे में आ जाओ, अभी आवाज चेक कर लेते हैं। गाना रिकार्ड करने में हमें सुबह के चार-पांच बज गए। मैं यही सोच रही थी कि वह केवल मेरी आवाज चेक कर रहे हैं। मैंने कहा कि मैं एक-दो दिन में आ जाऊंगी, कुछ बदलाव करने होंगे तो बताना। एक महीना निकल गया, उनकी तरफ से कोई फोन ही नहीं आया। मुझे लगा कि मेरी जगह किसी और को इस गाने के लिए ले लिया है।

खेल समाचार

ईडन गार्डन्स में रिंकू सिंह का धमाका

आखिरी ओवर में छक्का जड़कर केकेआर को दिलाई सीजन की पहली जीत

ईडन गार्डन्स,19 अप्रैल 2026। आईपीएल 2026 में आखिरकार कोलकाता नाइट राइडर्स का इंतजार खत्म हुआ। लगातार हार के बाद, केकेआर ने अपने घरेलू मैदान ईडन गार्डन्स पर राजस्थान रॉयल्स को 4 विकेट से हराकर सीजन की अपनी पहली जीत दर्ज की है। इस जीत के महानायक एक बार फिर रिंकू सिंह बने, जिन्होंने आखिरी ओवर में अपने बल्ले का दम दिखाते हुए टीम को फिनिशिंग लाइन के पार पहुंचाया। कोलकाता के लिए यह जीत केवल दो अंक नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की वापसी है। सीजन के शुरुआती मैचों में लगातार असफलता झेलने के बाद, इस जीत ने केकेआर को पॉइंट्स टेबल में खाता खोलने का मौका दिया है। ईडन गार्डन्स के दर्शकों के लिए रिंकू सिंह का यह फिनिश पुराने सुनहरे दिनों की याद दिलाने वाला रहा।

रिंकू सिंह और अनुकूल रॉय की मैच जिताऊ साझेदारी

156 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए कोलकाता की शुरुआत बेहद खराब रही थी। कप्तान अजिंक्य रहाणे और टिम सीफर्ट के सस्ते में आउट होने के बाद एक समय केकेआर ने 85 रन पर 6 विकेट गंवा दिए थे। यहाँ से रिंकू सिंह (53 रन) और अनुकूल रॉय (29 रन) ने मोर्चा संभाला। दोनों के बीच हुई 50 से अधिक रनों की नाबाद साझेदारी ने मैच का पासा पलट दिया।

आखिरी ओवर का रोमांच: रिंकू का विनिंग छक्का

मैच अंतिम ओवर तक खिंचा, जहाँ केकेआर को जीत के लिए रनों की दरकार थी। रिंकू सिंह ने संयम बनाए रखा और 20वें ओवर की चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़कर टीम को शानदार जीत दिलाई। रिंकू ने 34 गेंदों में 53 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 2 छक्के शामिल रहे।

मैच का परिणाम:- केकेआर 4 विकेट से जीता

जीत के हीरो : रिंकू सिंह (53 रन) और वरुण चक्रवर्ती (3 विकेट)। सीजन की स्थिति:- केकेआर की 6 मैचों में यह पहली जीत है।इस जीत के साथ केकेआर ने अंक तालिका में अपनी स्थिति में सुधार किया है। अब टीम का अगला मुकाबला मनोबल के साथ होगा। वहीं, राजस्थान रॉयल्स को अपनी मध्यक्रम की बल्लेबाजी और डेथ ओवरों की गेंदबाजी पर मंथन करना होगा। रविवार का दूसरा मुकाबला लखनऊ और पंजाब के बीच जारी है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हैं।

चोटिल म्हात्रे आईपीएल से बाहर होंगे बाहर

चेन्नई,19 अप्रैल 2026। चेन्नई सुपर किंग्स को अपने निराशाजनक उन्नीसवें सीज़न में एक और झटका लगा, जब एक अहम बैटिंग खिलाड़ी आयुष मात्रे जांघ की मसल में चोट के कारण आईपीएल के बाकी मैच से बाहर हो सकते हैं। इस टैलेंटेड बैट्समैन को शनिवार को उप्पल स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच के दौरान चोट लगी, जिससे फैंस और टीम प्ले-ऑफ में अपने चांस को लेकर परेशान हो गए। 195 रन के टारगेट का पीछा करते हुए, मात्रे क्रीज पर आए और कई बाउंड्री लगाकर अपने पावर-प्ले का हुनर दिखाया। हैदराबाद के पेसर प्रफुल्ल हिंगे के एक ज़बरदस्त ओवर में, मात्रे ने पांच चौके मारे। हालांकि, दूसरा रन लेने की कोशिश में, उनकी बाईं जांघ की मसल में अचानक खिंचाव आ गया। फिजियो के तुरंत ध्यान देने के बावजूद, मात्रे आगे नहीं खेल सके और आखिरकार क्लासेन के डाइविंग कैच से आउट हो गए। उन्हें चलने में साफ तौर पर दिक्कत हो रही थी और सपोर्ट स्टाफ की मदद से उन्हें मैदान से बाहर ले जाना पड़ा।

रियल सोसिएदाद ने पेनल्टी शूटआउट में एटलेटिको मैड्रिड को हराकर कोपा डेल रे का खिताब जीता

मैड्रिड,19 अप्रैल 2026। रियल सोसिएदाद ने पेनल्टी में एटलेटिको मैड्रिड को हराकर कोपा डेल रे का टाइटल जीता,जिससे अमेरिकी कोच पेलेग्रिनो माटाराज़ो को इस सीज़न में स्पेन आने के बाद अपना पहला करियर टाइटल मिला। एक्स्ट्रा टाइम के बाद गेम 2-2 से बराबर होने के बाद,सोसिएदाद के गोलकीपर उनाई मारेरो ने अलेक्जेंडर सोरलोथ और जूलियन अल्वारेज़ के शॉट बचाए, और पाब्लो मारिन ने आखिरी किक को गोल में बदलकर शूटआउट 4-3 से जीत लिया। 48 साल के माटाराज़ो ने कहा,यह एक अविश्वसनीय सफ़र रहा है,और मुझे लगता है कि यह बस शुरुआत हो सकती है। आप सफलता की कल्पना करते हैं,और आप अपने खिलाड़ियों पर भरोसा करते हैं, लेकिन जब तक आप लाइन पार नहीं करते,आपको इसका एहसास नहीं होता। उस पेनल्टी के साथ,मुझे इसे महसूस करने में कुछ पल लगे,और यह हमारे खिलाड़ियों और स्टाफ के लिए बहुत खुशी की बात थी। सोसिएदाद को किकऑफ़ के ठीक बाद एंडर बैरेनेटेक्सिया के ज़रिए बढ़त लेने के लिए 14 सेकंड और सिर्फ़ तीन खिलाड़ियों की ज़रूरत थी। न्यू जर्सी में जन्मे माटाराज़ो ने दिसंबर में सोसिएदाद को संभाला था,जब वह स्पैनिश लीग में रेलीगेशन ज़ोन से दो पॉइंट ऊपर था। चार महीने बाद,बास्क कंट्री क्लब ने कप जीत लिया है और ला लीगा टेबल के ऊपरी आधे हिस्से में है। एटलेटिको अब अपना ध्यान इस महीने के आखिर में शुरू होने वाले आर्सेनल के खिलाफ चैंपियंस लीग सेमीफ़ाइनल पर लगाएगा। हमने 1-0 और 2-1 से वापसी की और हमारे पास इसे जीतने के मौके थे। हम केवल अपने विरोधी को बधाई दे सकते हैं, जो खास मौकों पर ज़्यादा क्लिनिकल था,÷ शिमोन ने कहा, जो आखिरी मिनटों में एलेक्स बेना के पॉइंट-ब्लैंक मिस के बाद अपने हाथों और घुटनों के बल नीचे गिर गए और उनका सिर थोड़ी देर के लिए टर्फ से दब गया। ऑप्टा स्टैटिस्टिक्स ने कहा कि बैरेनेटेक्सिया का गोल स्पैनिश कप फ़ाइनल में अब तक का सबसे तेज़ गोल था। एटलेटिको के शानदार डिफेंस के खिलाफ पहला गोल बहुत आसान था। गोलकीपर के पास बॉल, दाएं फ्लैंक से लंबी बॉल, जहां गोंसालो गुएडेस के पास एंडर बैरेनेटेक्सिया के लिए क्रॉस भेजने का मौका था, जिसने उसे हेडर से गोल में डाल दिया।

बायर्न म्यूनिख के फॉरवर्ड सर्ज ग्नाब्री के बाकी सीज़न से होंगे बाहर

बायर्न,19 अप्रैल 2026। म्यूनिख के फॉरवर्ड सर्ज ग्नाब्री शायद बाकी सीज़न नहीं खेल पाएंगे, जिससे जर्मनी के लिए वर्ल्ड कप में उनका हिस्सा लेना मुश्किल हो गया है। ग्नाब्री की दाहिनी जांघ की एडिक्टर मसल फट गई है और वह लंबे समय तक बाहर रहेंगे,बायर्न ने शनिवार को यह घोषणा की। क्लब ने और कोई जानकारी नहीं दी, जिससे चोट कितनी गंभीर है और 30 साल के फॉरवर्ड की वापसी का समय पक्का नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि वह बायर्न के सीज़न के बाकी गेम नहीं खेल पाएंगे क्योंकि टीम तीन ट्रॉफियां जीतने की कोशिश में है। बायर्न के रविवार को बुंडेसलीगा का टाइटल जीतने की संभावना है,अगर वह स्टटगार्ट से अपने घर में नहीं हारता है,तो उसके पास ट्रॉफी पक्की करने के लिए चार और राउंड होंगे। इसके बाद बायर्न का सामना बुधवार को जर्मन कप सेमीफाइनल में बायर लेवरकुसेन से होगा, जिसके बाद वह चैंपियंस लीग सेमीफाइनल में पेरिस सेंट-जर्मेन पर ध्यान देगा। पिछले वीकेंड बायर्न ने बुंडेसलीगा में गोल करने का रिकॉर्ड तोड़ते हुए ग्नाब्री ने आठ गोल किए और सात और गोल में मदद की। उन्होंने जर्मनी के लिए हर वर्ल्ड कप क्वालिफायर और मार्च में दो फ्रेंडली मैचों में शुरुआत की। मेक्सिको, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स में होने वाले टूर्नामेंट के लिए कोच जूलियन नैगल्समैन के प्लान में उन्हें ज़रूर शामिल किया गया होगा।

आईपीएल 2026 में सीएसके की जीत के बाद ईशान किशन ने एसआरएच की युवा तिकड़ी की तारीफ़

चेन्नई,19 अप्रैल 2026। चेन्नई सुपर किंग्स पर अपनी टीम की जीत के बाद, सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान इशान किशन अपने युवा और कम अनुभवी बॉलिंग लाइन-अप के शानदार प्रदर्शन से खुश हैं,लेकिन उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि टीम को अपने शॉट सिलेक्शन में बेहतर होने की ज़रूरत है। अभिषेक शर्मा और हेनरिक क्लासेन की शानदार फिफ्टी के बाद, इशान मलिंगा, साकिब हुसैन, प्रफुल हिंगे और नीतीश कुमार रेड्डी और स्पिनर शिवांग कुमार के युवा पेस अटैक की बारी थी,जिन्होंने 195 रन का डिफेंस किया। प्रफुल ने पावर प्ले में रन दिए, लेकिन बॉलर्स ने पारी के दूसरे हाफ में सीएसके बैटिंग लाइन-अप पर दबाव बनाए रखा, जिससे सीएसके 10 रन पीछे रह गई। मैच के बाद बात करते हुए, इशान ने कहा,जब आपके पास कई युवा बॉलर्स अपने प्लान के साथ आते हैं तो यह बहुत अच्छा लगता है। उन्हें [प्रफुल,साकिब,शिवांग],ट्रेनिंग में दिन-ब-दिन बेहतर होते हुए देखें,आपको उन पर भरोसा करना होगा। उन्होंने कहा,मुझे लगा कि हम 30-40 रन पीछे रह गए, हमें अपने शॉट सिलेक्शन में और बेहतर करने की ज़रूरत है। पॉइंट्स टेबल को नहीं देख रहा,हमें शांत रहना होगा,हम एक बार में एक मैच के बारे में सोचेंगे और देखेंगे कि क्या होता है।

नकली दवा कांड : कार्रवाई से ज्यादा जांच पर सवाल, सिस्टम की साख दांव पर

कार्रवाई करने वाला कठघरे में, जांच करने वाले सवालों से बाहर क्यों?

नकली दवा केस में उलझी कहानी : जब्ती, जांच और जिम्मेदारी सब संदिग्ध

एक ही केस, दो तरह की कार्रवाई-नकली दवा कांड में न्याय पर सवाल

जांच या आत्म-जांच? विवादित अधिकारियों के हाथ में पूरा मामला

ढाई लाख बनाम 25 लाखः आंकड़ों के खेल में फंसा नकली दवा कांड

गायब दुकान, मौजूद जांच—प्रेम प्रकाश एजेंसी केस में बड़ा सवाल

कार्रवाई की आड़ में विरोधाभासः नकली दवा कांड में कौन जिम्मेदार?

नकली दवा नेटवर्क पर चोट या सच पर परदा? जांच पर उठे गंभीर सवाल

एनएसयूआई का विरोध एक पर क्यों? पूरे सिस्टम पर चुप्पी क्यों?

-न्यूज डेस्क-

रायपुर, 19 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)। छत्तीसगढ़ में सामने आया नकली दवा कांड अब एक साधारण आपराधिक मामला नहीं रह गया है, यह प्रकरण धीरे-धीरे एक ऐसे जटिल घटनाक्रम में बदल गया है, जहां कार्रवाई, जांच और विरोध–तीनों ही अपने-अपने स्तर पर सवालों के घेरे में हैं, एक ओर विभाग अपनी कार्रवाई को बड़ी सफलता के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, वहीं दूसरी ओर जांच की निष्पक्षता, आंकड़ों की पारदर्शिता और राजनीतिक संगठनों की भूमिका को लेकर गंभीर संदेह उभर रहे हैं, यह मामला अब केवल नकली दवाओं के नेटवर्क तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता और जवाबदेही की परीक्षा बन गया है। नकली दवा कांड अब केवल अवैध दवाओं की जब्ती और गिरफ्तारी तक सीमित मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली, जांच की निष्पक्षता और राजनीतिक संगठनों की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला प्रकरण बन चुका है, शुरुआत में इसे एक बड़ी कार्रवाई और संगठित नेटवर्क के खुलासे के रूप में प्रस्तुत किया गया, लेकिन जैसे-जैसे परतें खुलती गईं, मामले ने एक जटिल और विरोधाभासी रूप ले लिया, सबसे अहम बात यह है कि जिस कार्रवाई से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, उसी कार्रवाई से जुड़े अधिकारी को अब मुख्य रूप से निशाने पर लिया जा रहा है। यह स्थिति अपने आप में सवाल खड़ा करती है कि क्या जवाबदेही तय करने का दायरा सीमित किया जा रहा है? क्योंकि जांच के दौरान सामने आए तथ्यों में कई ऐसे बिंदु हैं, जो केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरी प्रक्रिया और उसमें शामिल अन्य अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की मांग करते हैं, मामले में जब्ती के आंकड़ों में भारी अंतर, जांच के समय और परिस्थितियों को लेकर उठते सवाल, और एक ही प्रकरण में अलग-अलग स्तर पर की गई कार्रवाई–ये सभी पहलू संकेत देते हैं कि मामला सतही नहीं, बल्कि गहराई से समझे जाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही, जांच में शामिल कुछ अधिकारियों पर पहले भी कार्रवाई हो चुकी होने के बावजूद उन्हें ही पुनः जिम्मेदारी सौंपे जाने से निष्पक्षता को लेकर संदेह और बढ़ जाता है, दूसरी ओर, इस पूरे घटनाक्रम में राजनीतिक संगठन एनएसयूआई की भूमिका भी चर्चा का विषय बन गई है। संगठन द्वारा उठाई जा रही आवाज जहां एक ओर जवाबदेही की मांग करती दिखती है, वहीं दूसरी ओर यह आरोप भी उभर रहा है कि विरोध केवल एक व्यक्ति तक सीमित कर दिया गया है। इससे यह धारणा बनती है कि पूरे सिस्टम की बजाय एक सीमित दायरे में सवाल उठाए जा रहे हैं, ऐसे में यह मामला केवल नकली दवाओं का नहीं, बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता की परीक्षा बन गया है, अब जरूरत इस बात की है कि सवाल किसी एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर समान रूप से उठें, ताकि सच्चाई सामने आए और जनता का भरोसा कायम रह सके।

कार्रवाई की कहानी शुरुआत गोगांव गोल्डन ट्रांसपोर्ट से शुरू होती

10 दिसंबर 2025 को रायपुर के गोगांव स्थित गोल्डन ट्रांसपोर्ट से नकली दवाओं की बड़ी खेप जब्त की गई, इस कार्रवाई को अंजाम दिया था सहायक औषधि नियंत्रक संजय नेताम ने एक ऐसी कार्रवाई, जिसे उस समय विभाग ने अपनी 'बड़ी सफलता' के रूप में प्रस्तुत किया, विडंबना यहीं से शुरू होती है, जिस अधिकारी की पहल पर यह पूरा मामला सामने आया, वही आज इस प्रकरण में निलंबित है, आधिकारिक भाषा में यह 'प्रशासनिक कार्रवाई' हो सकती है, लेकिन घटनाक्रम को देखने वाले इसे एक अलग नजर से पढ़ रहे हैं जैसे किसी तैयार पटकथा में नायक को ही बीच में खलनायक बना दिया गया हो, यदि उस दिन संजय नेताम कार्रवाई नहीं करते, तो संभवतः यह पूरा नेटवर्क परतों के नीचे ही दबा रह जाता और विभाग के पास आज अपनी 'सफलता' का कोई आधार भी नहीं होता, लेकिन व्यवस्था की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं और कभी-कभी वे प्राथमिकताएं परिणाम से ज्यादा भूमिकाओं को तय करती हैं, यहां एक ऐसा चक्रव्यूह नजर आता है, जिसमें प्रवेश तो कार्रवाई करने वाले अधिकारी ने किया, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता शायद पहले से तय नहीं था, सवाल यह नहीं है कि कार्रवाई सही थी या गलत, बल्कि यह है कि उसके बाद घटनाओं की दिशा किसने तय की, विभाग ने इस जब्ती को संगठित नेटवर्क के खुलासे के रूप में पेश किया और यहीं से इस पूरे मामले की कहानी शुरू हुई। लेकिन जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती गई, हर नया अध्याय अपने साथ नए सवाल लेकर आता गया–और सबसे पहला सवाल उसी बिंदु पर खड़ा हो गया, जहां से यह कहानी शुरू हुई थी।

जांच से पहले प्रेम प्रकाश एजेंसी दुकान गायब कैसे हुआ था?

इस पूरे प्रकरण में सुरेन्द्र कमनानी की प्रेम प्रकाश एजेंसी एक ऐसा केंद्र बिंदु बनकर उभरती है, जिसने मामले को साधारण जांच से उठाकर संदेह और व्यंग्य के दायरे में ला खड़ा किया, दिलचस्प तथ्य यह है कि यदि दैनिक घटती-घटना समाचार-पत्र इस एजेंसी को लेकर लगातार खबरें प्रकाशित नहीं करता, तो संभवतः यह नाम भी उन फाइलों में दबा रह जाता, जहां कई मामले धीरे-धीरे 'ठंडे' हो जाते हैं, लगातार खबरों और सवालों के बाद ही प्रशासन हरकत में आता है और प्रेम प्रकाश एजेंसी पर कार्रवाई की दिशा बनती है, लेकिन तब तक घटनाक्रम एक अलग ही मोड़ ले चुका होता है, जांच से ठीक पहले दुकान का रातों-रात खाली हो जाना इस पूरे मामले का सबसे रहस्यमय हिस्सा बन जाता है, अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, लेकिन सामने सिर्फ एक खाली दुकान होती है न दवाओं का कोई निशान, न कारोबार का कोई प्रमाण, यहीं से यह कहानी अपने सबसे व्यंग्यात्मक रूप में प्रवेश करती है, ईश्वरी नारायण सिंह को जांच की जिम्मेदारी मिलती है, और वे अपने 'करीबी सहयोगी' नीरज साहू को उसके छुट्टी के दिन साथ लेकर पहुंचते हैं, खाली दुकान में बैठकर जांच की औपचारिकता पूरी की जाती है, मानो सब कुछ नियमों के तहत हो रहा हो, फिर इस पूरे घटनाक्रम की तस्वीरें सामने आती हैं, और उसके बाद कार्रवाई की दिशा तय होती है, यानी पहले दृश्य सार्वजनिक होता है, फिर निर्णय आकार लेता है यह क्रम खुद ही कई सवालों को जन्म देता है, लगातार मीडिया दबाव खासतौर पर दैनिक घटती-घटना की रिपोर्टिंग के बाद प्रेम प्रकाश एजेंसी और उससे जुड़े इंदौर स्थित मां बिजासन मेडिकोज पर कार्रवाई होती है, लेकिन सवाल अब भी वहीं खड़ा है क्या यह कार्रवाई समय पर हुई, या तब जब अब बचाव की संभावनाएं खत्म हो चुकी थीं? सबसे बड़ा और असहज प्रश्न अब भी हवा में तैर रहा है दुकान खाली होने की सूचना किसे पहले थी? और अगर थी, तो वह बाहर कैसे पहुंची? इस 'गायब' दुकान ने इस पूरे मामले में जितने तथ्य उजागर किए, उससे कहीं ज्यादा संदेह पैदा कर दिए–और शायद यही इस कहानी का सबसे सटीक सार है।

गिरफ्तारी हुई, लेकिन क्या पूरा नेटवर्क सामने आया?

जांच के दौरान तीन प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार किया गया रोचक अग्रवाल (बिजासन मेडिकोज, इंदौर), सुरेन्द्र कमनानी (प्रेम प्रकाश एजेंसी, भाटापारा) खेमराज बानी (सरस्वती मेडिकल स्टोर, सारंगढ़) विभाग का दावा है कि यह कार्रवाई नेटवर्क की रीढ़ तोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम है, लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है क्या यही पूरा नेटवर्क है? या अभी भी कई नाम सामने आना बाकी हैं?

कार्रवाई से खुला मामला, लेकिन कार्रवाई करने वाला ही सवालों में...

इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत 10 दिसंबर 2025 को रायपुर के गोगांव स्थित गोल्डन ट्रांसपोर्ट से नकली दवाओं की बड़ी खेप की जब्ती से हुई, इस कार्रवाई को सहायक औषधि नियंत्रक संजय नेताम ने अंजाम दिया, उस समय इसे विभाग की बड़ी सफलता के रूप में प्रचारित किया गया और इसे एक संगठित नेटवर्क के खिलाफ बड़ी उपलब्धि बताया गया, लेकिन घटनाक्रम ने जल्द ही एक अलग मोड़ ले लिया, जिस अधिकारी की पहल पर यह पूरा मामला सामने आया, वही बाद में निलंबन की कार्रवाई का सामना करता है, यह स्थिति कई सवाल खड़े करती है क्या कार्रवाई करने वाला अधिकारी ही सबसे बड़ी गलती का जिम्मेदार है, या फिर मामला कुछ और संकेत दे रहा है? यह विरोधाभास पूरे प्रकरण की दिशा को समझने के लिए अहम बन जाता है।

जब्ती के आंकड़ों में बड़ा अंतर...

इस मामले में सबसे ज्यादा चर्चा जब्त दवाओं की कीमत को लेकर हो रही है, एक ओर दावा किया जा रहा है कि जब्ती करीब 25 लाख रुपये की थी, वहीं दस्तावेजों में यह आंकड़ा घटाकर लगभग 2.25 लाख रुपये दर्शाया गया है, यह अंतर केवल एक तकनीकी त्रुटि नहीं माना जा सकता, यदि यह गलती है, तो यह असामान्य है, और यदि यह जानबूझकर किया गया है, तो यह गंभीर अनियमितता का संकेत देता है, यह मुद्दा पूरे मामले की विश्वसनीयता को सीधे प्रभावित करता है।

जांच उन्हीं के हाथ में...जिन पर पहले उठे सवाल

मामले का सबसे विवादित पक्ष जांच अधिकारियों को लेकर सामने आता है, ड्रग इंस्पेक्टर ईश्वरी नारायण सिंह और नीरज साहू को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है, आरोप यह है कि इन्हीं अधिकारियों पर पहले इसी मामले में लापरवाही के चलते कार्रवाई हो चुकी है और उनकी वेतन वृद्धि रोकी गई थी, ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या पहले से विवादित अधिकारी ही निष्पक्ष जांच कर सकते हैं? यह स्थिति पूरे प्रकरण को 'जांच या आत्म-जांच' जैसे सवालों की ओर ले जाती है।

छुट्टी के दिन जांच और बढ़ते संदेह

एक और पहलू जो लगातार चर्चा में है, वह है छुट्टी के दिन जांच का किया जाना, बताया जाता है कि नीरज साहू, जो उस समय अवकाश पर थे, वे ईश्वरी नारायण सिंह के साथ प्रेम प्रकाश एजेंसी की जांच में शामिल हुए, सामान्य परिस्थितियों में इसे तत्परता के रूप में देखा जा सकता था, लेकिन जब पूरा मामला पहले से विवादित हो, तो यही कदम संदेह को और गहरा करता है, खासकर तब, जब जांच स्थल पर कोई ठोस साक्ष्य मौजूद ही नहीं था।

कार्रवाई में असमानता : एक ही मामले में अलग-अलग सजा

इस पूरे प्रकरण में कार्रवाई के स्तर पर भी असमानता देखने को मिली है, ईश्वरी नारायण सिंह और नीरज साहू पर केवल वेतन वृद्धि रोकने की कार्रवाई की गई, जबकि रायगढ़ के अधिकारियों अमित राठौर और विजय राठौड़ को निलंबित कर दिया गया, यह अंतर कई सवाल खड़े करता है क्या सभी की जिम्मेदारी समान नहीं थी? यदि मामला एक ही है, तो कार्रवाई अलग-अलग क्यों? यह स्थिति प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाती है।

जांच टीम की भूमिका भी सवालों में...

इस कार्रवाई में डॉ. सुरेश कुमार साहू और डॉ. टेकचंद धीरहे की भी भूमिका रही है, हालांकि मुख्य विवाद अन्य अधिकारियों को लेकर है, लेकिन जांच एक सामूहिक प्रक्रिया होती है, इसलिए पूरी टीम की भूमिका पर भी सवाल उठना स्वाभाविक है।

नकली दवा कांड में बड़ा खुलासा...जिन पर शक, उन्हीं के हाथ में जांच!
चार महीने बाद गिरफ्तारी, लेकिन सवाल बरकरार-क्या जांच निष्पक्ष होगी?
नकली दवाओं से ज्यादा 'जांच सिस्टम' पर संकट, विभागीय गुटबाजी आई सामने....

एनएसयूआई की भूमिका: विरोध या चयनात्मक सवाल?

इस पूरे मामले में राजनीतिक संगठन एनएसयूआई की भूमिका भी चर्चा का विषय बन गई है। संगठन द्वारा संजय नेताम पर कार्रवाई की मांग उठाई गई है, लेकिन यह विरोध एक व्यक्ति तक सीमित नजर आता है, यहां सवाल यह है कि क्या विरोध केवल एक अधिकारी के खिलाफ होना चाहिए? क्या पूरे सिस्टम की जांच की मांग नहीं उठनी चाहिए? वर्तमान स्थिति यह संकेत देती है कि विरोध व्यापक नहीं है, बल्कि सीमित दायरे में केंद्रित है। इससे संगठन की निष्पक्षता पर भी सवाल उठ रहे हैं।

जनता के भरोसे पर असर

नकली दवाओं का मामला सीधे जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा होता है। ऐसे में यदि जांच प्रक्रिया पर ही सवाल उठने लगें, तो इसका असर केवल इस केस तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे सिस्टम पर जनता के भरोसे को प्रभावित करता है, जब कार्रवाई से ज्यादा चर्चा जांचकर्ताओं और प्रक्रिया पर होने लगे, तो यह स्थिति किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए चिंताजनक होती है।

जवाब अभी बाकी है...नकली दवा कांड में कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी हुई, जांच जारी है...

लेकिन इसके बावजूद सबसे बड़ा सवाल अब भी अनुत्तरित है—क्या यह जांच निष्पक्ष और पारदर्शी है? जब तक इस सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं मिलता, यह मामला केवल एक आपराधिक केस नहीं रहेगा, बल्कि यह प्रशासनिक व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर एक गंभीर प्रश्न बना रहेगा।

फिलहाल, पूरे घटनाक्रम का सबसे स्थायी और आधिकारिक जवाब यही है— 'जांच जारी है... '

कोरबा के रविंद्र पाराशर बने छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष...

बिलासपुर, 19 अप्रैल 2026। कोरबा के वरिष्ठ अधिवक्ता रविन्द्र कुमार पाराशर ने एक बार फिर अपनी कार्यकुशलता और नेतृत्व क्षमता का लोहा मनवाया है। छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल के चुनाव में उन्हें अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित किया गया है। पूर्व में भी उनके द्वारा स्टेट बार में महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए पूर्ण निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया है। रविन्द्र पाराशर का स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष पद पर निर्वाचन कोरबा जिले के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। वर्षों से विधि के क्षेत्र में अपनी निष्ठा और ईमानदारी के लिए पहचाने जाने वाले पाराशर ने न केवल स्थानीय बार एसोसिएशन, बल्कि पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं के बीच अपनी एक खास जगह बनाई है। उनके अध्यक्ष बनने से राज्य के हजारों वकीलों को एक अनुभवी और संवेदनशील नेतृत्व मिला है। अपने करियर में रविंद्र कुमार पाराशर ने हमेशा अधिवक्ताओं के हितों और न्यायपालिका की गरिमा को सर्वोपरि रखा है। उनकी कार्यशैली और अनुशासन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत रही है। अधिवक्ताओं के बीच उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मतदाताओं ने उन पर भरोसा जताते हुए यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। अध्यक्ष पद की कमान संभालते ही पाराशर के कंधों पर राज्य के अधिवक्ताओं के कल्याण, जूनियर वकीलों के लिए सुविधाओं का विस्तार और राज्य भर के अधिवक्ताओं व अधिवक्ता संघों से संबंधित महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आ गई है। उनके नेतृत्व में उम्मीद जताई जा रही है कि स्टेट बार काउंसिल नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा।

महिला आरक्षण बिल गिरने पर कांग्रेस के खिलाफ उतरेगी बीजेपी...

70 करोड़ महिलाओं की उम्मीदें टूटीं : सीएम साय

रायपुर, 19 अप्रैल 2026। नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में पास नहीं होने के बाद भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन करेगी। इसी कड़ी में लगातार छत्तीसगढ़ में भी विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन होंगे। रायपुर में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि 70 करोड़ महिला शक्ति की उम्मीदों पर पानी फेरा गया, वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरूण सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने महिलाओं के अधिकारों के साथ गद्दारी की है।

अरुण सिंह बोले...यह विपक्ष की काली करतूत

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने अपनी 'काली करतूत' का परिचय दिया और बिल पास नहीं होने दिया। जब भी महिला अधिकार की बात आई, कांग्रेस ने महिलाओं के अधिकारों के साथ गद्दारी की है और हमेशा उनके हितों की उपेक्षा की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने महिला बिल को फाड़ने तक का काम किया। समाजवादी पार्टी और आरजेडी ने हमेशा महिलाओं को गाली देने का काम किया। महिलाओं को इस बार पूरी आशा थी कि बिल पास हो जाएगा, लेकिन बिल गिरने पर विपक्ष के लोगों ने तालियां बजाई और खुशियां मनाई, जबकि भाजपा के लोगों की आंखों में आंसू थे। अरुण सिंह ने कहा कि कांग्रेस के लोग चालबाज हैं और कांग्रेस ने विपक्षी दलों के साथ मिलकर बहुत बड़ा पाप किया है, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। संशोधन में दो-तिहाई बहुमत चाहिए था, इसलिए उम्मीद थी कि कांग्रेस और विपक्ष समर्थन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुछ लोग समर्थन करना चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा नहीं होने नहीं दिया। जो नासमझ हो उसे समझाया जा सकता है, लेकिन जो समझकर भी न समझे, वही काम कांग्रेस कर रही है। भाजपा के संविधान में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का उल्लेख है।

लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान (131वां संशोधन) बिल पास नहीं हो सका। बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि 230 सांसदों ने इसके विरोध में मतदान किया।

इसे पारित करने के लिए 352 वोटों की आवश्यकता थी। इस बिल में लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर 816 करने और महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान शामिल था।

कांग्रेस फूट डालो और राज करो की नीति अपनाती है : सीएम साय

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि वे बहुत दुखी मन से मीडिया के बीच आए हैं और 33 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण विपक्ष के रवैये की वजह से नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन ने 70 करोड़ महिला शक्ति की उम्मीदों पर पानी फेरने का काम किया है। सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पंचायती राज में महिलाओं का आरक्षण 57 प्रतिशत है और विधानसभा में भी 21-22 प्रतिशत नारी शक्ति है। इंडी गठबंधन के लोग अंग्रेजों की तरह 'फूट डालो और राज करो' की नीति अपनाते हैं और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टी धर्म के नाम पर आरक्षण की बात कहकर लोगों को बरगलाती है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इंडी गठबंधन को इसका खामियाजा भुगतना होगा। कांग्रेस और इंडी गठबंधन का वास्तविक चेहरा सामने आ चुका है और देश की माता-बहनें सच्चाई जान चुकी हैं।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफसेट प्रिंटर्स, नमनाकला, संत हरकेवल विद्यापीठ के पास, अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050, डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001, 98265-32611, Email:ghatatighatana11@ gmail.com, Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)